विषय सूची

हरियाणा विधानसभा चुनाव
भाजपा ने फूंका चुनावी बिगुल. 5
विशेष रिपोर्ट.......................... 21

लेख
किसान को हक चाहिए
– राजकुमार सिंह......... 9
सूखे से लड़ने के लिए कस लें कमर
– टी. हक.............. 11
दीनदयालजी ने अपनी कर्मठता से.
– नानाजी देशमुख......... 14
वैश्वीकरण की दिशा एवं दशा
– डा. संजय पासवान.... 18

अन्य
प्रधानमंत्री को पत्र.................... 7
महिला मोर्चा रा.का. बैठक....... 12
संप्रग सरकार के 100 दिन.... 16
मणिपुर : गृहमंत्री को ज्ञापन... 25

प्रदेशों से
दिल्ली............................... 4
गुजरात............................. 19
झारखण्ड.......................... 20
मध्यप्रदेश.......................... 23
चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़.......... 28
उत्तराखण्ड, हिमाचल......... 29

सम्पादक
çHkkr >k] lkln
सम्पादक मंडल
lR;iky
d- d- 'kek
lathо dqekj flUgk
पृष्ठ संयोजन
/keZUæ dkS'ky
सम्पर्क
Mk- eqdthZ Lefr U;kl
ihih&66] lqcze.;e Hkkjrh ekxZ
ubZ fnYyh&110003
Qksu ua- +91¼11½&23381428
QSDl % +91¼11½&23387887
lnL;rk gsrq % +91¼11½&23005700
सदस्यता शुल्क
okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-
e-mail address
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

सम्पादकीय

मनुष्य केवल अपने कर्तव्य का पालन करे तो अन्य कोई साधन किए बिना कल्याण हो जाएगा।

-श्रीरामसुखदासजी महाराज

न मर्यादाएं टूटनी चाहिए, न वर्जनाएं

b न दिनों भारतीय जनता पार्टी अखबारों की सुर्खियों में है। हम इसको दूसरे अर्थों में लेते हैं। मीडिया भी चाहता है कि भाजपा अन्य दलों से भिन्न और अलग पहचान वाली पार्टी के रूप में दिखे। पत्रकार भी दुखी हैं तो भाजपा, जिससे समाज को भी बहुत आशाएं है, अगर वह पार्टी समाज और राष्ट्र के अनुरूप नहीं दिखे तो उसका मन भी आहत होता है। वहीं कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो भाजपा को स्वयं चलाना चाहते हैं। यह बात तो समझ में आती है कि आप सलाह दें, पर ये कैसे संभव हो पाएगा कि ''आप'' जो कहें, पार्टी वही करे।

स्थिति तब और बदतर हो जाती है जब विचारधारा के ''शब्दस्तम्भ'' बनकर समाज के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करने वाले 'मूड' बिगाड़ लेते हैं और फिर 'वो' कलम से भाजपा को ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। कमरे में कहने वाली बातें, कलम से सार्वजनिक तौर पर नहीं कहना चाहिये। पर वे पत्रकार भी क्या करें? उन पर उनकी पत्रकारिता हावी रहती है। वे चाहकर भी अपने को रोक नहीं पाते। उनकी प्रकृति है अपनी बात किसी भी तरह रखना। अब बात तो यही है कि बात तो रखनी चाहिए, पर कब, कहां और कैसे? यह 'समझ' तो अपने उन 'शब्दस्तंभों' को बताना होगा जो राष्ट्रवादी विचाराधारा के वाहक हैं।

राजनीति' में पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी स्तरों के मित्रों से राजनेताओं का घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक है। संबंध होता भी है, होना भी चाहिए। राजनैतिक कार्यकर्ता और पत्रकारों के बीच संबंध होना अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन उनके साथ सदैव निश्चित निकटता एवं निश्चित दूरी रहनी चाहिए। पर ऐसा नहीं हो पाता। दूरियां घटती हैं। मर्यादाएं टूटती हैं, वहीं निकटताएं बढ़ती हैं। तब ही वर्जनाएं टूटती हैं। मर्यादाएं और वर्जनाएं नहीं टूटनी चाहिए।

मर्यादा और वर्जना का टूटना खतरे से खाली नहीं होता। स्थिति भयावह हो जाती है। पत्रकार कभी किसी व्यक्ति या नेता के उपकरण बन जाएं, यह न उस नेता के लिए अच्छा होता है और न ही उस पत्रकार के लिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि न पत्रकार नेता का

हथियार बने और न ही नेता पत्रकार की ढाल बने। होना तो यह चाहिए कि वे एक दूसरे के पूरक रहें।

पत्रकारिता' का धर्म राष्ट्र प्रहरी का है। कार्यकर्ता का धर्म देश और दल का प्रहरी होना भी है। फिर स्थिति यह हो जाती है जो 'शब्दस्तम्भ' होते हैं, वे कार्यकर्ता नहीं बन पाते, या अपने को कार्यकर्ता के रूप में ढाल नहीं पाते। 'वे' स्वयं को सदैव विशेष मानते रहते हैं। जबकि देश के कार्यकर्ताओं में उनके प्रति यह भावना बलवती होती रहती है कि ये तो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं का सोचना भी गलत नहीं है क्योंकि वे 'शब्दस्तम्भ' सदैव वरिष्ठों के बीच रहते हैं। उन्हें जो सम्मान मिलता है, वह अतुलनीय एवं अमूल्य है।

अतः मीडिया के उन वर्गों का जो हमारा विरोध करने के लिए ही पत्रकार हैं, उनसे तो भाजपा या राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए काम करने वाले संगठनों को कोई खतरा नहीं रहता पर खतरा उनसे जरूर होने लगता है, जो अब तक कलम से विचाराधारा के लिए आग उगलते रहे हैं। हमें लगता है कि पत्रकारिता कभी ''मित्रकारिता'' नहीं हो सकती। अतः हमें अपने दायरे को समझ, राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति अपने-अपने स्थानों पर राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह भी करना होगा। ■

जनता ने झटका हाथ, दिया कमल का साथ

नगर निगम उपचुनाव में भाजपा को तीन व कांग्रेस को एक सीट, एक निर्दलीय

नगर निगम चुनाव उपचुनाव में चार सीटों पर करारी हार से कांग्रेस को करारा झटका लगा है, वहीं भाजपा तीन सीटें जीतकर जश्न में डूब गई। भाजपा ने दो सीटें मयूर विहार व हस्तसाल कांग्रेस से छीनी हैं तथा आनंद विहार सीट पर अपना वर्चस्व बरकरार रखने में कामयाब रही है। दिचाऊकलां सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार किशन पहलवान ने कब्जा किया है। दो सीटें खोकर कांग्रेस को नुकसान हुआ है। कांग्रेस केवल समयपुर बादली सीट बचाने में कामयाब हुई। दिल्ली में कांग्रेस को मिली इस शिकस्त का लाभ भाजपा को दिल्ली में हो रहे उप-चुनाव में भी होगा।

हस्तसाल वार्ड : हस्तसाल वार्ड में भाजपा प्रत्याशी विजय सोलंकी ने अपने निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी को 2308 वोटों से हराया। यहां विजय सोलंकी को 14802 मत और कांग्रेस के राकेश को 12494 मत मिले। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी शिव कुमार को 3604 मत मिले, जबकि 1908 मत लेकर निर्दलीय इस्लाम चौथे स्थान पर रहे।

जीत के बाद झूमकर नाचे भाजपा कार्यकर्ता

आनंद विहार और मयूर विहार सीट के नतीजे आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने मतगणना केन्द्र के बाहर ही जोरदार आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया। बाद में कार्यकर्ताओं ने दोनों वार्डों में घूमकर नगाड़ों और ढोल की थाप पर खूब जश्न मनाया।

मयूर विहार वार्ड : मयूर विहार वार्ड में भाजपा के देवेन्द्र कुमार 3170 मतों से विजयी हुए हैं। उन्हें कुल 9344 मत हासिल हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र 6366 मत हासिल हुए। इसके अलावा एक अन्य उम्मीदवार क्रिश नंद शास्त्री को 222 मत हासिल हुए।

आनंद विकार वार्ड : आनंद विहार वार्ड 225 से भाजपा के महेन्द्र जैन ने कांग्रेस के रतन सिंह को 469 मतों से हराया। भाजपा प्रत्याशी महेन्द्र जैन को कुल 5678 मत हासिल हुए, जबकि कांग्रेस के रतन सिंह को 5209 मत मिले। एक अन्य उम्मीदवार जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी की सुनीता चौधरी को मात्र 84 मत हासिल हुए।

दिचाऊं कलां वार्ड : दिचाऊंकलां वार्ड संख्या 139 में भाजपा और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी किशन पहलवान 5183 वोटों से जीतने में सफल रहे हैं। इस वार्ड में कांग्रेस के पदम सिंह 6743 मत लेकर दूसरे स्थान पर जबकि भाजपा के संदीप शौकीन 4970 मत लेकर तीसरे स्थान पर रहे हैं।

समयपुर बादली वार्ड : समयपुर बादली वार्ड में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर के बाद आखिरकार कांग्रेस प्रत्याशी एए दीपक चौधरी 4260 मतों से विजयी होने में सफल रहे। इस वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी को 12289 मत मिले, वहीं भाजपा प्रत्याशी अनूप यादव को 8029 मत मिले। इसके अलावा निर्दलीय कुमर सिंह मात्र 216 मत हासिल करने में कामयाब रहे। ■

कमल संदेश

भाजपा ने फूंका चुनावी बिगुल

जब-जब कांग्रेस सत्ता में आयी महंगाई बढ़ाई : राजनाथ सिंह

dkग्रेस जब भी सत्ता में आती है महंगाई अपने साथ लेकर आती है। अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल प्रधानमंत्री रहे लेकिन महंगाई को नहीं बढ़ने दिया, जिस कारण आम आदमी उनके शासनकाल को आज भी याद करता है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय श्री अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने 6 सितम्बर को स्थानीय छोटूराम स्टेडियम में आयोजित पार्टी के राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कही। इस सम्मेलन में प्रदेश के कोने–कोने से आए भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

सम्मेलन में चुनाव शंखनाद करते हुये श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस महंगाई के लिए वैश्विक आर्थिक मंदी को जिम्मेदार ठहरा रही है जबकि हकीकत यह है कि महंगाई जमाखोरी और कालाबाजारी का परिणाम है, जिसे कांग्रेस की शह मिली हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित प्रदेशों में चार प्रतिशत से भी कम दर पर किसानों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार तो किसानों को खेतीबाड़ी के लिए इस वर्ष से मात्र एक प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने पर यहां भी किसानों को वैसी ही सुविधा दी जायेंगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी सरकार आने पर किसानों के लिए कृषि आमदनी बीमा योजना लागू की जायेगी जिसके अंतर्गत हर खेत की न्यूनतम आमदनी पच्चीस हजार रूपये तय की जायेगी। उन्होंने कहा कि हम केवल सत्ता लेने के लिए राजनीति नहीं करते बल्कि देश व समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सदैव जाति व धर्म की राजनीति की है व सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी जिन्ना और उनकी विचारधारा का हमेशा ही विरोध करती रही है। भाजपा जिन्ना को हमेशा देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार मानती है और इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है।

रविवार को रोहतक में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में जसवंत सिंह की किताब के मुद्दे पर पार्टी के रूख को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इसको लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए। पार्टी राष्ट्रवाद और एकात्मक मानववाद की मूल विचारधारा पर कायम है और इसमें किसी प्रकार की बदलाव की कोई आशंका नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा से हटकर, जिन्होंने जिन्ना की प्रशंसा की, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। भाजपा कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्णपाल गुज्जर ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार विपक्ष का मजाक उड़ा रहे हैं, उससे उनका अहंकार झलकता है। उन्होंने कहा कि हुड्डा को यह याद होना चाहिए कि यही कांग्रेस 1977 मे तीन तथा 1987 में 5 सीटों तक सिकुड़ गई थी। यही नहीं 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने प्रदेश से कांग्रेस का सफाया कर दिया था। उन्होंने कहा कि हुड्डा को लोकसभा चुनाव परिणामों के भ्रम में नहीं रहना चाहिए।

भाजपा के प्रदेश प्रभारी विजय गोयल ने कहा कि भाजपा वंशवाद व परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती जबकि अन्य दलों की बुनियाद ही परिवारवाद पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ब्लॉक स्तर से राजनीति शुरू करके पार्टी के शिखर पर पहुंचे हैं। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सरदार हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि कांग्रेस व अन्य क्षेत्रीय दलों ने प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है। भाजपा विधायक दल के नेता नरेश मलिक ने कहा कि भाजपा ने विपक्ष में रहकर रचनात्मक सहोग दिया है लेकिन प्रदेश सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इनेलो से नाता तोड़ा है। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन को प्रो. गणेशीलाल, आत्मप्रकाश मनचंदा, रतनलाल कटारिया, ओमप्रकाश धनखड़, सुधा यादव कै. अभिमन्यु, मनीष ग्रोवर, प्रदीप जैन, कंवल सिंह सैनी आदि नेताओं ने भी सम्बोधित किया।■

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी का निधन

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 60 वर्षीय येदुगुरि संदिन्ती राजशेखर रेड्डी का गत 2 सितम्बर को हैदराबाद के पास कुरनूल में एक हेलीकाप्टर दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। श्री रेड्डी चित्तूर में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह करीब 8.30 बजे हैदराबाद से रवाना हुए थे, लेकिन करीब 9.30 बजे मौसम खराब होने के बाद हेलीकाप्टर का नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क टूट गया और इसके करीब 26 घंटे बाद सघन तलाशी अभियान में कुरनूल से करीब 40 किलोमीटर दूर जंगली इलाके में हेलीकाप्टर का मलबा और बुरी तरह जले हुए शव पाए गए। उस दिन श्री रेड्डी के साथ उनके प्रमुख सचिव सुब्रह्मण्यम, मुख्य सुरक्षा अधिकारी जान वैसली और दो पायलट थे। मुख्यमंत्री के निधन की खबर से न केवल आंध्र प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में शोक की लहर फैल गयी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने श्री रेड्डी के अकस्मात निधन पर गहन शोक प्रकट करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी।

एक प्रशिक्षित चिकित्सक डा. राजशेखर रेड्डी को राजनीतिक क्षेत्र में लोग वाई.एस.आर. के नाम से पुकारते थे। अभी मई, 2009 में आंध्र प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 1956 में राज्य के गठन के बाद वे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने न केवल पांच साल का कार्यकाल पूरा किया था बल्कि चुनावों में फिर से सत्ता हासिल की थी। कभी कोई चुनाव न हारने वाले वाई. एस.आर. पांचवीं बार विधानसभा के लिए चुनाव जीते थे, जबकि इससे पहले चार बार लोकसभा सांसद रह चुके थे। जुलाई 1949 में कडप्पा जिले के एक छोटे से शहर में एक ईसाई परिवार में जन्मे वाई.एस.आर.ने गुलबर्गा (कर्नाटक) के एम.आर. कालेज से चिकित्सक की उपाधि ली थी।

भारतीय जनता पार्टी ने भी पार्टी कार्यालय में अपना ध्वज आधा झुका कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी अंतिम यात्रा में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी सम्मिलित हुए एवं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

अटल बिहारी वाजपेयी

io ç/kkue=h

3 सितम्बर को माननीय अटलजी ने अपने शोक संदेश में कहा कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस.राजशेखर रेड्डी के दुःखद निधन के समाचार से मुझे बहुत आघात पहुंचा है। डॉ. रेड्डी एक कर्मठ, ऊर्जावान और संभावनाओं से भरे समर्पित राजनीतिज्ञ थे। उनके निधन से आन्ध्र प्रदेश ने एक प्रगतिशील नेता खो दिया। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे। इस विमान दुर्घटना में मारे गए उनके चार सहयोगियों के प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

लालकृष्ण आडवाणी

ykd lHkk e foi{k d urk

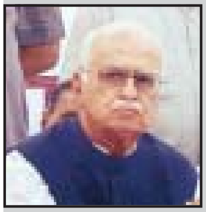

मुझे यह जानकर गहरा दुःख हुआ है कि हेलीकाप्टर दुर्घटना में आंध्रप्रदेश के मुख्य मंत्री डा. वाईए. एस. रेड्डी एवं उनके साथ जा रहे अधिकारियों और हेलीकाप्टर के दो चालकों की मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु से आंध्र प्रदेश तथा पूरे देश के लोगों ने एक बहुत ही योग्य तथा लोकप्रिय नेता को गंवा दिया है। आंध्र प्रदेश के विकास में तथा विशेष रूप से समाज के अपवंचित वर्गों के विकास में उनका योगदान बड़ा सराहनीय रहा है। विगत छह वर्षों में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की। सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी लोगों के लिए उतना ही प्रशंसनीय कार्य किया था। जनता तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम अपने हाथ में लिए थे, जिनमें से विशेष रूप से वर्ष 2003 में उनकी 1400 कि.मी. की पदयात्रा उल्लेखनीय है। मैं उनके असामयिक एवं दुखद निधन के प्रति हार्दिक शोक व्यक्त करता हूं। दो अधिकारियें तथा हेलीकाप्टर के दो चालक सदस्यों के प्रति भी मैं उनके प्रियजनों की इस क्षति पर हार्दिक शोक प्रगट करता हूं। ईश्वर, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

राजनाथ सिंह

jk"Vªh; v/;{k] Hkktik

मुझे श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के असामयिक निधन के समाचार से हार्दिक दुख हुआ है। श्री रेड्डी ने गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया था। वह उन नेताओं में से थे जो गरीबों की सेवा करने में विश्वास रखते थे। उनके आकस्मिक निधन से देश में एक गहरी शून्यता भर दी है और विशेष रूप से आंध्र के लोगों के लिए तो यह बड़ी भारी क्षति है। मैं शोकसंतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रगट करता हूं। ■

कमल संदेश

सूखे की मार से किसानों को बचाने के लिए त्वरित उपाए किए जाएं: राजनाथ सिंह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने देश में सूखे की स्थिति के नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए कृषि उत्पादन पर भारी चिंता व्यक्त की है। अतः उन्होंने इस ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए विशेष उपाए करने पर बल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को 30 अगस्त को एक पत्र लिखकर अपनी गहन चिंता जताई है। हम इस पत्र का पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं।

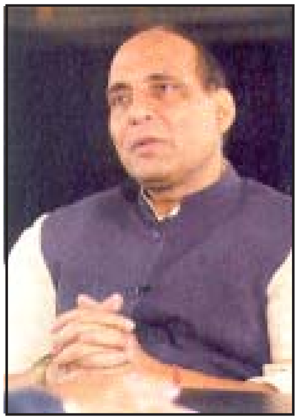

प्रिय प्रधानमंत्री जी

नमस्कार!

जलवायु परिवर्तन और इसका हमारी जनता, कृषि और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से हम सब भली भाँति परिचित है। इस वर्ष, करीब 250 जिलों को सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 10 फीसदी तक की गिरावट की संभावना जतायी जा रही है। वित्त मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि इन सब कारणों से देश की अर्थव्यवस्था के लिए 6 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर दर्ज करना संभव नही दिख रहा है।

सबसे दुःखद बात तो यह है कि हमारे किसान जिनमें से अधिकांश सीमान्त और छोटे किसान है तथा उनमें से भी अधिकांश काफी गरीब हैं वे संकट से सबसे बुरी तरह पीड़ित है। मौसम की मार के कारण किसानों के लिए लागत और उत्पादन के असंतुलन का खतरा पैदा हो गया है और जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं के कारण से इन चुनौतियों के सम्मुख अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। इस कारण वे और अधिक संकटों में घिरते जा रहे हैं।

मैं समझता हूं कि भारत और उसके पड़ोसी दक्षिण एशियाई देश विश्व में जलवायु परिवर्तन की समस्या से सर्वाधिक पीड़ित देशों में गिने जाते है। एक अनुमान के अनुसार इक्कीसवीं शताब्दी के अन्त तक भारत के औसत वार्षिक तापमान में 3 डिग्री से 6 डिग्री तक तथा औसत वर्षा में 15 से 40 फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है परन्तु यह वर्षा काफी असंतुलित और असामान्य रहेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार तापमान में इस वृद्धि का सर्वाधिक असर उत्तर भारत पर पड़ेगा जो भारत के लिए खाद्यान्न का टोकरा माना जाता है। प्रति एक डिग्री तापमान में वृद्धि के कारण गेहूं उत्पादन में 40 से 50 लाख टन की कमी की आशंका जताई जा रही है।

खरीफ के मौसम में सूखे (इस वजह से आगामी रबी की फसलों के लिए भी जल उपलब्धता पर असर पड़ने की आशंका हैं) और रबी के मौसम में अधिक तापमान के कारण हमारे देश की धान और गेहूं आधारित अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ेगी। इसके चलते हमारी खाद्य सुरक्षा और देश की कृषि सम्पन्नता पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसलिए इस संकट की धार कुंद करने के लिए समाज के सभी वर्गों जिनमें सरकार, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, आम जनता तथा किसानों का एक गठबंधन बना कर काम करने की आवश्यकता है।

मुझे ज्ञात है कि हाल ही में भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया है, जिसमें Mission on sustainable Agriculture भी सम्मिलित है उसमें जलवायु परिवर्तन के अनुसार ढालने की क्षमता विकसित करने के सन्दर्भ में कुछ निर्देश दिये गये है। इन सारी बातों और तमाम सद्भावनाओं के वावजूद हम यह जानते है कि समय बहुत ही कम बचा है। जहां एक और नीति और योजना बनाने वाले लोग अभी औपचारिक कार्य योजना ही बनाने में लगे हुए हैं वही समय की मांग है कि हम आज ही इस दिशा में काम प्रारम्भ कर दें। कुछ दिनों पहले आपने स्वयं इस संदर्भ में आपातकालीन योजना बनाने और विफल मानसून के प्रतिकूल परिणामों के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए कार्ययोजना बनाने का सुझाव रखा था।

कमजोर मानसून के कारण खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है जिसके कारण गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए भूख का संकट गहरा हो गया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए नाम मात्र या सांकेतिक मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की तत्काल व्यवस्था बनाये।

कृषि के संकट से निपटने के लिए कई सुझाव और कार्य योजनायें प्रस्तावित की जा चुकी हैं जिसमें राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा दिये गये सुझाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सुझावों को जमीनी स्तर पर लागू किये जाने की आवश्यकता है। इन सुझावों में National Risk Fund, Market Stabilization Fund, National Soil

and Water Board और Indian Trade Organisation की स्थापना और गठन के साथ किसानों को विशेष रूप से छोटे किसानों तथा गरीबों को बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम से बचाने की व्यवस्था करने की भी बात कही गई है।

सूखे, बाढ़ और सामान्य मौसम के लिए एक तर्कसंगत संहिता का निर्माण किया जाना चाहिए। ग्रामीण बीज बैंक, खाद्यान्न बैंक, चारा बैंक, जलाशयों तथ ज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने से किसानों को संभावित जलवायु परिवर्तन के संबंध में पूर्व चेतावनी के साथ–साथ उन्हें संभावित खतरों से भी जल्द ही आगाह कर सकते है।

इसके लिए हर ब्लॉक में एक प्रशिक्षित पुरूष और एक महिला Climate Change Management Agent की नियुक्ति की जा सकती है जो ग्रामीणों को इस संबंध में मौके पर ही जानकारी दे सकेंगे।

चूँकि इस प्रक्रिया में लघु, मध्यम और दीर्घ कालीन उपायों को विकसित करने के लिए सही तकनीक विकसित करनी पड़ेगी इसलिए देश में अनुसंधान, तकनीक निर्माण तथा तकनीक हस्तांतरण की एक सुनिश्चित व्यवस्था खड़ी करनी होगी। इस व्यवस्था का एक मानवीय चेहरा हो और विकासोन्मुख होने के साथ–साथ यह भी ध्यान रखे कि संसाधनविहीन गरीबों की आवश्यकतायें क्या है?

इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढालने के लिए बने अनुसंधान और तकनीक एजेंडा में एक मजबूत मानिटरिंग, मूल्यांकन और प्रभावों की समीक्षा करने के साथ बीच राह में सुधार करने का Mechanism भी शामिल होना चाहिए।

कृषि के इस गहराते संकट से तत्काल निपटने के लिए एक दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। इस देश के गरीब और किसान अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमें आज से ही इस संकट से निपटने के लिए काम करना प्रारम्भ करना होगा। भाजपा यह मांग करती है कि एक National Task Force on Adaptation to Climate Change and Sustainable Agriculture का तत्काल गठन किया जाना चाहिए ताकि कृषि के संबंध में सभी सुझावों एवं समस्याओं को त्वरित एवं संवेदनशील ढंग से सम्बोधित और निष्पादित किया जा सके।

सादर।

¼jktukFk flag½■

हाईकोर्ट में केन्द्र ने माना :

लश्कर से जुड़े थे इशरत और उसके साथी

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात हाईकोर्ट में गत छह अगस्त को दाखिल हलफनामे में यह स्वीकार कर लिया है कि अहमदाबाद पुलिस के हाथों 15 जून, 2004 को दो पाकिस्तानी नागरिकों के साथ मारी गई इशरत जहां और उसका साथी जावेद शेख वास्तव में आतंकवादी संगठन लश्कर–ए–तैयबा से जुड़े थे। इशरत जहां मुंबई के खालसा कॉलेज की छात्रा थी, जबकि जावेद शेख उर्फ प्रणेश कुमार पिल्लई मुंबई के ठाणे का निवासी था।

इशरत जहां की मां शमीमा कौसर की एक याचिका के जवाब में केन्द्र सरकार को अहमदाबाद हाईकोर्ट में यह शपथ पत्र देना पड़ा। इसमें सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि 'केन्द्र को यह सूचना मिली थी कि लश्कर–ए–तैयबा भारत के शीर्ष स्तर के केन्द्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं की हत्या करने की फिराक में है और उसने भारत स्थित अपने काडर से ऐसे नेताओं की निगरानी करने को कहा है।'

केन्द्र सरकार और उसकी एजेंसियों ने हलफनामे में बताया है कि इस जानकारी को संबंधित राज्य सरकारों तक भी पहुंचा दिया गया था। राज्य सरकारों से सूचनाओं के आदान–प्रदान के तहत ही केन्द्र सरकार को यह पता चला कि लश्कर ने अपने काडर को यह निर्देश दिए हैं कि वे कुछ खास आतंकवादी गतिविधियां करें। इन काडर में गुजरात में छिपे हुए कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल थे। गुजरात में आतंकवादी हमले की योजना के संदर्भ में जावेद शेख लश्कर के आतंकवादियों खासकर मुजामिल उर्फ तारिक के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए था। केन्द्र के हलफनामे से अहमदाबाद पुलिस द्वारा बताए इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि भारत में बब्बर, सलीम, राजकुमार राणा आदि बदले हुए नाम से ठहरने वाला अमजद अली और जीशान जौहर वास्तव में पाकिस्तानी नागरिक थे। इन दोनों को भी अहमदाबाद एनकाउंटर के दौरान मारा गया था।

हलफनामे में कहा गया है, '15 जून, 2004 को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए लोगों में से दो

पाकिस्तानी नगारिक थे और यह पता चला है कि उन्हें लश्कर–ए–तैयबा ने गुजरात में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए भेजा था। जम्मू–कश्मीर पुलिस ने 25 से 28 जून के भीतर लश्कर के 18 आतंकवादियों के एक समूह को गिरफ्तार किया था जिसका नेतृत्व लश्कर का केन्द्रीय कश्मीर के लिए चीफ ऑपरेशनल कमांडर शाहिद महमूद और उसका पाकिस्तानी सहयोगी जाहिद अहमद कर रहा था।' ■

साभार : ई.टाइम्स

किसान को हक चाहिए, खैरात नहीं

& jktdekj flg

ekनसून इस साल बेवफा निकला। देर से आया, कम बरसा और जल्दी लौट जाने के संकेत भी मिल रहे हैं। इसका सीधा असर जनजीवन, खासकर खेती पर पड़ा है, क्योंकि आजादी के 63 साल बाद भी हमारी 60 प्रतिशत खेती बारिश के पानी पर निर्भर हैं। 200 से भी ज्यादा जिले सूखे की चपेट में हैं। जाहिर है, सूखे की सीधी और जबरदस्त मार किसानों, खासकर धान उत्पादक किसानों पर पड़ी है, क्योंकि धान की फसल को पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। सूखे की मार किसान पर दोहरी पड़ी है। एक ओर बुर्वा का क्षेत्र कम हो गया है तो दूसरी ओर लागत बढ़ गयी है। जाहिर है, देर–सवेर इस दोहरी चुनौती से देश और समाज को भी रूबरू होना ही पड़ेगा।

फिलहाल केन्द्र सरकार ने किसानों को राहत देने के नाम पर धान, दाल और तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का ऐलान किया है। निश्चय ही मनमोहन सिंह सरकार की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन यह देर से उठाया गया आधा–अधूरा कदम ही है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है तो अरहर व मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह वृद्धि क्रमशः 300 व 240 रूपये प्रति क्विंटल है। तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 100 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गयी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस वृद्धि पर किसान संगठनों और कई राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया से ही जाहिर है कि यह वृद्धि उनकी उम्मीद से ही नहीं, बल्कि जायज जरूरत से भी कम है।

धान के समर्थन मूल्य में 100 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गयी है तो दालों के मामले में यह वृद्धि 300 रूपये तक है। इस बार विलंब से आये मानसून में भी कमी का सबसे ज्यादा असर धान की खेती पर पड़ता नजर आ रहा है। वैसे भी धान की फसल को अधिक पानी की जरूरत होती है। बहुत विलंब से आकर भी नाममात्र को बरसे मानसून की बेरूखी के परिणामस्वरूप ही देशभर में इस बार धान की रोपाई का क्षेत्रफल सामान्य से 20 प्रतिशत कम रह गया है। जाहिर है, इसका सीधा असर धान के उत्पादन पर भी पड़ेगा ही। यह समस्या का एक पहलू है, जो आने वाले महीनों में भयावह रूप में सामने आयेगा। समस्या का दूसरा पहलू है मानसून में कमी के कारण धान की फसल की बढ़ी हुई लागत। जो फसल टिकी ही पानी पर होती है, मानसून की बेरूखी की स्थिति में उसकी लागत कितनी अधिक बढ़ गयी होगी, इसका अनुमान लगा पाना ज्यादा मुश्किल तो नही होना चाहिए, पर केन्द्र सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में मात्र 100 रूपये प्रति क्विंटल की ही वृद्धि की है। सामान्य श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 850 से बढ़ाकर 950 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि उच्च श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य अब 880 से बढ़कर 980 रूपये प्रति क्विंटल हो गया है। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह वृद्धि कितनी कम है, इसका अंदाजा किसान संगठनों ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया से भी लगाया जा सकता है।

किसान संगठन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1500 रूपये प्रति क्विंटल किये जाने की मांग कर रहे थे, तो पंजाब समेत कुछ राज्यों ने इसमें 300 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की मांग की थी, लेकिन तमाम दरियादिली का दावा करते हुए भी केन्द्र ने महज 100 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का ही ऐलान किया है। इसलिए अगर किसान संगठनों को यह वृद्धि एक क्रूर मजाक लगती है तो गलत भी नहीं है। मानसून के विलंब से आगमन और कम बारिश के चलते धान की रोपाई में किसानों की लागत कितनी बढ़ गयी होगी तथा आने वाले दिनों में भी कुल लागत कितनी बढ़ जायेगी, इसको ही धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का आधार बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया है।

इस मामले में किसानों की प्रतिक्रिया सबसे अहम और विश्वसनीय होनी चाहिए। अगर उन्हीं के संगठनों की मानें तो बारिश के अभाव में इस बार किसानों को जिस तरह डीजल का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा है, उससे धान की लागत ही 1500 रूपये क्विंटल तक पहुंच गयी है। फिर 950 रूपये या 980 रूपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो उनके जख्मों पर नमक मलने के समान ही हुआ। किसानों को कम मूल्य दिये

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है तो अरहर व मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह वृद्धि क्रमशः 300 व 240 रूपये प्रति क्विंटल है। तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 100 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गयी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस वृद्धि पर किसान संगठनों और कई राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया से ही जाहिर है कि यह वृद्धि उनकी उम्मीद से ही नहीं, बल्कि जायज जरूरत से भी कम है।

जाने के पक्ष में अकसर तर्क दिया जाता है कि सरकार को आम उपभोक्ता का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। बेशक सरकार को सभी का ध्यान रखना ही चाहिए, पर यह काम किसान का पेट काटकर क्यों किया जाता है? किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य देने के नाम पर तो सरकार किंतु–परंतु करने लग जाती है, लेकिन बाद में विदेशों से दोगुने मूल्य पर खाद्यान्न आयात किया जाता है। जाहिर है, इस विरोधाभासी खेल के पीछे खिलाड़ियों के अपने निहितार्थ ही प्रभावी रहते हैं। पूरे वर्ष प्रतिकूल मौसम में हाड़तोड़ मेहनत करके किसान जो फसल उगाता है, उसका लाभकारी मूल्य उसका हक है, जो उसे मिलना ही चाहिए।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा धान व दाल के समर्थन मूल्यों में वृद्धि के इस फैसले का ऐलान करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने विश्वास जताया था कि किसानों को इससे राहत मिल पायेगी, लेकिन किसान संगठनों और कृषि प्रधान राज्यों की प्रतिक्रियाएं इससे मेल नहीं खाती। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा का मूल मकसद है कि किसान को किसी भी घाटे की स्थिति से बचाया जाये तथा इसकी घोषणा बुवाई का सीजन शुरू होने से पहले कर दी जाये ताकि किसान अगली फसल की बुवाई से पहले आश्वस्त हो जाये कि उसे अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिल पायेगा और वह घाटे में नहीं रहेगा। इसी हिसाब–किताब के आधार पर वह भी फैसला कर पाये कि उसे कितने क्षेत्र में कौन सी फसल बोनी है।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के गठन का उद्देश्य भी निश्चय ही यह रहा होगा कि वह संबंधित फसल की लागत और किसान परिवार की मेहनत आदि को ध्यान में रखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करेगा, ताकि किसानों को घाटा न हो। जाहिर है, फसल की बुवाई शुरू हो जाने या फिर पूरी हो जाने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा और वह भी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश से बहुत कम किये जाने की प्रवृत्ति से ये दोनों ही उद्देश्य पूरे नहीं होते। ऐसे में कम से कम सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर तो केन्द्र सरकार का रवैया अधिक मानवीय होना चाहिए।

वैसे तो धान, दाल व तिल के समर्थन मूल्य में वृद्धि को ऐलान करते हुए चिदंबरम ने यह भी कहा था कि सरकार कदम–दर–कदम आगे बढ़ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि केन्द्र सरकार सूखे के चलते किसान पर पड़ने वाली दोहरी मार से उसे राहत पहुंचाने के लिए कुछ और कदम समर्थन मूल्य में और वृद्धि अथवा बोनस आदि की घोषणा के रूप में उठायेगी, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं भी करती है तो राज्य सरकारों को भी आगे आकर किसानों को राहत देने में अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए।

दरअसल यह भी समस्या का तात्कालिक इलाज ही है। स्थायी इलाज तो यही होगा कि कृषि के प्रति सरकार अपना सौतेला व्यवहार बदले। देश के सकल घरेलू उत्पाद में 21 प्रतिशत भागीदारी होने तथा आज भी आधी से अधिक आबादी जीवनयापन के लिए कृषि पर ही निर्भर होने के बावजूद ऐसा क्यों है कि कृषि के लिए इस कृषि प्रधान देश में कोई दीर्घकालीन नीति नहीं बनायी जाती? आजादी के 63 साल बाद भी 60 प्रतिशत खेती बारिश पर निर्भर होना और दूसरों का पेट भरने वाले किसानों द्वारा आत्महत्या का अंतहीन सिलसिला क्या इसी सौतेले व्यवहार का प्रमाण और परिणाम नहीं है? अकसर उद्योगों और उद्योगपतियों के हित संवर्धन की चिंता में ही डूबे रहने वाले हमारे राजनेताओं और नौकरशाहों को समझना होगा कि किसान को खैरात नहीं, अपना हक चाहिए। ■

(साभार)

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को दुर्गापूजा व दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

सत्य की असत्य पर विजय

सूखे से लड़ने के लिए कस लें कमर

& Vh- gd

देश वर्ष 2009–2010 में भारी सूखे का सामना करने सजा रहा है। खरीफ सीजन में जून से अगस्त तक देश के कई हिस्से में कम बारिश से इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जून से सितंबर तक देश के 330 जिलों में या तो कम या फिर छिटपुट बारिश हुई है। सिर्फ 152 जिलों में सामान्य बारिश देखने को मिली। सामान्य बारिश 731.7 मिमी. की तुलना में 565.3 मिमी. बारिश हुई है। दस राज्यों के 262 जिलों में सूखा से प्रभावित घोषित कर दिया गया है।

वास्तव में इस सूखे की तीव्रता और विस्तार 1965, 1987 और 2002 के सूखे से ज्यादा हो सकता है। इन वर्षों के दौरान देश का 43 से 49 फीसदी हिस्सा सूखे की चपेट में था। वर्ष 2002–2003 में देश में खाद्यान्न उत्पादन 3.80 करोड़ टन कम हुआ था। जबकि कृषि जीडीपी गिरकर 35269 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस तरह के असर के मामले में इस बार का सूखा भी कम साबित नहीं होगा। ताजा अनुमानों के मुताबिक चार सितंबर तक धान के रकबे में 63 लाख हेक्टेयर की कमी आ चुका था। धान की उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर 2.1 टन पर बनी हुई है। रकबे में कमी की वजह से इसकी उत्पादकता 13.40 करोड़ टन पर आ टिकने के आसार हैं। सूखे की इस भयानक स्थिति में आखिर क्या किया जाए जिससे हालात थोड़ा संभल सके।

सबसे पहले तो हमें भोजन, चारे और पानी की व्यवस्था करना होगा। यह सभी चीजें हर घर में पहुंचानी होगी ताकि सूखे का मानव और पशु जीवन पर कम से कम असर हो। पिछले सप्ताहों के दौरान खाद्य वस्तुओं पर आधारित महंगाई नौ से चौदह फीसदी तक थी। अब इसमें और इजाफा हो सकता है। हालात तो इतने खराब हो सकते हैं कि कुछ इलाकों में पानी खरीदना पड़े। लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के पास पानी खरीदने की ताकत नहीं होगी। सूखे का छोटे और सीमांत किसानों की जीविका पर भारी असर पड़ेगा। भूमिहीन श्रमिक पर बेरोजगारी की मार पड़ेगी। छोटे और सीमांत किसान के बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। उनकी औरतों को कम खाना मिलेगा। पिछले उदाहरणों को देखें तो पाएंगे कि एक साल के सूखे का असर अगले कई साल तक जारी रहा है। इससे आर्थिक विकास और गरीबी निवारण में अड़चनें पैदा होती हैं।

सूखाग्रस्त इलाकों में निराशा के संकेत दिखने लगे हैं। अगस्त के महीने में ही विदर्भ और आंध्रप्रदेश से किसानों की आत्महत्या की खबरें आने लगी थीं। चारा और पानी की कमी वाले इलाके में मवेशियों को औने–पौने दाम पर बेचने की खबरें भी आने लगी हैं। इसलिए सरकार हो सक्रिय होकर ऐसे कदम उठाने हो गए जिससे सूखे चौतरफा प्रभाव को कम किया जा सके। लेकिन अभी तक की सरकार की कोशिश काफी लचर रही है।

सूखाग्रस्त इलाकों में निराशा के संकेत दिखने लगे हैं। अगस्त के महीने में ही विदर्भ और आंध्रप्रदेश से किसानों की आतमहत्या की खबरें आने लगी थीं। चारा ओर पानी की कमी वाले इलाके में मवेशियों को औने–पौने दाम पर बेचने की खबरें भी आने लगी हैं। इसलिए सरकार को सक्रिय होकर ऐसे कदम उठाने होंगे, जिससे सूखे चौतरफा प्रभाव को कम किया जा सके। लेकिन अभी तक की सरकार की कोशिश काफी लचर रही है। सरकार का कहना है कि उसके पास साढ़े चार करोड़ टन के अनाज के स्टॉक है, जिसे पीडीएस के जरिये बांट कर सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन यह सच्चाई है कि हमारा पीडीएस न सिर्फ अक्षम है बल्कि गैर असरदार और अपर्याप्त भी है। बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा और मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पीडीएस में पचास फीसदी की लीकेज हो जाती है। केंद्र सरकार इस भ्रम में भी है कि नरेगा से भूमिहीन किसानों को पर्याप्त रोजगार मिलेगा और उसे आमदनी हासिल होगी। लेकिन सरकारी आंकड़े ही इस बात की तसदीक करते हैं कि वर्ष 2006–2007 से लेकर 2008–2009 में सिर्फ 11 से 14 फीसदी लोगों को ही सौ दिनों का रोजगार हासिल हुआ।

यह बेहद निराशाजनक स्थिति है कि छह दशक के नियोजित विकास प्रणाली में हम जब–तब पैदा होने वाले सूखे के संकट का प्रभावी तौर पर सामना नहीं कर पाए हैं। अगर इस वक्त हमें सूखे से बेहतर तरीके निपटना है तो प्रशासनिक मशीनरी को चाक–चौबंद करके भोजन चारे और पानी की पुख्ता व्यवस्था करनी होगी। इसमें पंचायत और गैर सरकारी संगठनों मदद ली जा सकती है।

जहां भूजल स्तर सामान्य हो वहां, हल्की खुदाई या ट्यूबवेल के लिए बोरिंग की जा सकती है। तीसरा प्रबंध यह करना होगा कि सूखे से प्रभावित इलाकों में किसानों प्रति एकड़ चार हजार रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इन उपायों के अलावा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, कृषि इंश्योरेंस पॉलिसी और तकनीकी अपग्रेडेशन जैसे दीर्घकालिक उपाय अपनाने होंगे। ■

लेखक कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व चेयरमैन हैं। (साभार)

महिला आरक्षण मामले में केन्द्र सरकार ने झूठे वायदे किए : राजनाथ सिंह

Hkkरतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की द्वि–दिवसीय बैठक 8–9 सितंबर को नई दिल्ली में संपन्न हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने न तो चीन को उसके कृत्य पर कोई करारा जवाब ही दिया न समुचित कारवाई की। इन्हीं कारणों से चीन लुकाछिपी का खेल खेल रहा है। इस सरकार में सीमा सुरक्षा एवं देश के मान–सम्मान की रक्षा के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। इस सरकार ने सामाजिक समरसता को कुंठित किया है। यह सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। हम मजहब के आधार पर नही बल्कि गरीबी के आधार पर आरक्षण चाहते हैं। कांग्रेस भारत को और कितने टुकड़े में बांटना चाहती है। पाकिस्तान जब तक आतंकी गतिविधियों पर रोक नही लगाता है तब तक उससे कोई कूटनीतिक वार्ता नही होनी चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह विफल रही है। देश की अर्थव्यवस्था पर इस सरकार की प्रभावी पकड़ नहीं है। हर समय यह विश्व की आर्थिक मंदी का रोना रोती है। लेकिन केन्द्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय भी आर्थिक मंदी का दौर आया था किंतु सरकार द्वारा बनाई गई बड़ी–बड़ी योजनाओं के कारण जनता को इसका पता भी नही चला।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर केन्द्र सरकार कतई गंभीर नहीं है। यह सरकार सिर्फ झूठे वायदे करती है। इस सरकार ने पिछले पांच साल के कार्यकाल में महिलाओं से वादाखिलाफी की ही, 2009 के लोकसभा चुनाव में फिर महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया मगर उसे पूरा करने की कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नही दिखाई दे रही है। महिला मोर्चा को इसके लिए सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा।

पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम वेंकैया नायडू ने अपने संबोधन में कहा कि इस सरकार ने सौ दिनों के शासन काल में नाकामी का एक इतिहास रचा है। महिला आरक्षण को सौ दिनों के कार्य योजना में यूपीए सरकार ने रखा था, लेकिन इस दिशा में प्रगति शून्य है। सरकार सुरक्षा, पड़ोसी देशों से ताल्लुकात, महंगाई आदि को लेकर बिलकुल सोई हुई है। झारखंड में कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोंट रही है।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने किरण माहेश्वरी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं महंगाई के मुद्दे पर महिला मोर्चा आंदोलनरत रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार महिला आरक्षण पर विश्वासघात कर रही है, जबकि महिला देश की उन्नति का मूलाधार होती है।

भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक में राजनैतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया।

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी संप्रग सरकार द्वारा जन समस्याओं की सतत उपेक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीर अनदेखी की कड़ी भर्त्सना करती है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में संभवतः यह प्रथम अवसर है, जब आम निर्वाचन के मात्र 100 दिनों में ही जनता का नई सरकार से मोह भंग हो जाए।

संप्रग सरकार से मोह भंग

संप्रग सरकार की दूसरी पारी प्रारम्भ करते समय कांग्रेस दल ने बड़ी–बड़ी घोषणाएं की थी। किन्तु 100 दिनों के बाद आम जनता अपने को ठगी हुई अनुभव कर रही है। सरकार शासन के प्रत्येक मोर्चे पर बुरी तरह से असफल रही है। महंगाई, नक्सली हिंसा, बांग्लादेश का जनसांख्यिक आक्रमण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय हितों का लज्जास्पद समर्पण, पाकिस्तान द्वारा नकली भारतीय मुद्रा का मुक्त प्रसार ने संप्रग सरकार की शासन करने की क्षमता पर गम्भीर प्रश्न चिह्न खड़ा कर दिया है।

आम जनता का यह विश्वास बनता जा रहा है कि संप्रग सरकार को शासन करने का अवसर देना एक भारी भूल थी।

महंगाई की मार

भारतीय जनता महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अप्रत्याशित और अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि पर गहरी चिता व्यक्त करती है। अत्यधिक मूल्य वृद्धि भारतीय अर्थव्यव्यस्था का अभिशाप बन गई है।

किन्तु उस पर नियंत्रण करने के स्थान पर उचित ठहराने का प्रयास हास्यास्पद लगता है। गांव, गरीब, किसान और झोपड़ी में रहने वाले, बेतहाशा मूल्य वृद्धि से बेहाल है। वहीं एक छोटा वर्ग मालामाल हो रहा है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। 80 रूपए किलो में दालें, 70 से 90 रूपए किलो खाद्य तेल, 300 रूपए किलो घी, 35 रूपए किलो शक्कर, 20 रूपए किलों गेहूं, 25 से 80 रूपए किलो चावल, और 25 से 30 किलो दूध के भावों पर आम आदमी जीवन निर्वाह के

लिए न्यूनतम आवश्यक पोषक तत्व भी नहीं ले पा रहा है। केन्द्र सरकार मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के कोई प्रयास ही नहीं कर रही है। वे शून्य मुद्रा स्फीति की बातों से देश को भ्रमित कर रहे हैं। मूल्य वृद्धि का सबसे अधिक दुष्प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। अब तो सरकार सूखे और बाढ़ का बहाना लेकर महंगाई और बढ़ा रही है।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ठप्प पड़ी है। देश आवश्यक वस्तुओं की कमी झेल रहा है, किन्तु केन्द्र सरकार सो रही है। महिला मोर्चा सरकार से जनसाधारण को तात्कालिक राहत देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत समस्त कार्डधारियों को 30 रूपए प्रति किलो की दर से 5 किलोग्रम दाल और 15 रूपए प्रति किलो की दर से 5 किलो चीनी की आपूर्ति की मांग करता है।

महिला आरक्षण में धोखा

महिला आरक्षण पर कांग्रेस पार्टी दो चेहरे वाली पार्टी है। वे आरक्षण पर बोलते तो जोर शोर से हैं, किन्तु व्यवहार में करते कुछ नहीं हैं। संप्रग के पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में महिला आरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। 2008 में महिला मोर्चा ने दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया। पूरे भारत से आई 1.25 लाख से अधिक महिलाओं ने रैली में महिला आरक्षण की आवाज उठाई।

कांग्रेस को विवश होकर राज्य सभा में महिला आरक्षण का विधेयक प्रस्तुत करना पड़ा। किन्तु उसे कानून बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। लोकसभा चुनावों के घोषणा पत्र और 100 दिवसीय कार्य योजना में कांग्रेस ने विधायिका में एक तिहाई महिला आरक्षण का वादा किया था। अभी तक भी कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं। केन्द्र सरकार ने पहले 100 दिनों में महिला आरक्षण देने का बड़ा शोर किया था। महिला मोर्चा महिला सशक्तिकरण के इस अति महत्वपूर्ण विषय पर कांग्रेस के दोहरे चलन की कड़ी भर्त्सना करता है।

स्वागत, आशंका एवं अपेक्षा

केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण की स्वीकृति महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। भाजपा शासित राज्यों में तो पूर्व में ही पंचायतों एवं नगर निकायों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू कर दिया गया था। महिला मोर्चा पूरे देश में पंचायतों के साथ ही नगर निकायों में भी 50 प्रतिशत महिला आरक्षण करने की मांग करता है। यह आरक्षण केवल वार्ड सदस्यों तक ही नहीं हो कर संस्था प्रधानों के स्तर पर भी लागू होना चाहिए।

स्त्री शक्ति पुरस्कार

अटल बिहारी सरकार द्वारा स्त्री शक्ति पुरस्कारों का चलन प्रारम्भ करना एक ऐतिहासिक पहल थी। ये पुरस्कार महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और उनकी उपलब्धियों को सामने लाने के माध्यम हैं। कांग्रेसनीत संप्रग सरकार ने सत्ता में आते ही इन पुरस्कारों के चयन की प्रक्रिया को अपारदर्शी बना दिया, जो कि निंदनीय है। महिला मोर्चा इन पुरस्कारों को पारदर्शी एवं समयबद्ध करने की तत्काल घोषणा की मांग करता है।

प्रत्यक्ष कर संहिता में महिला करदाताओं की उपेक्षा

भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता में महिला, छोटे एवं वैतनिक करदाताओं के हितों की उपेक्षा पर रोष व्यक्त करता है। कांग्रेस सरकार ने वेतन से आय पर मिलने वाली मानक कटौती को समाप्त करके वैतनिक करदाताओं के साथ भारी अन्याय किया है। व्यापार से आय पर खर्चों की कटौती दी जाती है तो वेतन से आय पर क्यों नहीं?

महिला मोर्चा वैतनिक आय पर 50,000 रूपए की मानक कटौती देने, कर मुक्त आय सीमा बढ़ा कर 3 लाख रूपए करने, वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं के लिए कर मुक्त सीमा 4 लाख रूपए करने की मांग करता है।

महिला मोर्चा बचतों की निकासी पर कर लगाने का भी विरोध करता है। प्रत्यक्ष कर संहिता के अधिकांश प्रावधान वर्तमान आयकर कानून से ही लिए गए हैं। यह जनता पर कर भार बढ़ाने का उपक्रम मात्र है।

नरेगा योजना की सफलता का संप्रग सरकार द्वारा ढोल पीटा जा रहा है परन्तु जमीनी स्तर पर असलियत कुछ और है। इस योजना के तहत पुरूषों से अधिक महिलाओं का नियोजन हो रहा है, परन्तु इस योजना में विसंगतियों के रहते कार्यरत महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

महिला मोर्चा यह मांग करता है कि नरेगा योजना में कम से कम 200 दिन की मजदूरी मिले, महिलाओं के लिए विशेष पैकेज बनाया जाए। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं की संख्या शहरी क्षेत्र में भी है अतः इस योजना को शहरी क्षेत्र में भी लागू किया जाए। महिला मोर्चा की यह राष्ट्रीय कार्यसमिति संपूर्ण महिला समाज का आह्वान करती है कि महिलाओं के हित की अनदेखी करने वाली संप्रग की सरकार के कारनामे से सचेत रहें। कार्यसमिति अपनी लाखों कार्यकत्रियों को संदेश देती है कि वे अपने इर्दगिर्द समाज को संप्रग सरकार की महिला विरोधी नीतियों से अवगत कराए और यथोचित मांगों को लेकर संघर्ष करती रहें।

उपरोक्त भीषण परिस्थितियों को देखते हुए महिला मोर्चा यह संकल्प लेता है कि हम समाज में इन विषयों को लेकर चेतावनी सप्ताह के माध्यम से जन–जागरण करेंगे।

विभिन्न सत्रों में आयोजित हुई इस दो दिवसीय बैठक का समापन भाजपा की वरिष्ठ महिला नेता श्रीमती सुमित्रा महाजन के उद्बोधन से हुआ। उन्होंने अपने समापन भाषण में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में महिलाओं की विशेष भूमिका पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि वर्तमान यूपीए सरकार की कार्यप्रणाली महिला विरोधी है। फिर महंगाई हो या महिला आरक्षण या महिलाओं के साथ घटित होने वाली घटनाएं। इस सरकार में महिला असुरक्षित है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण संगठन में देकर एक संदेश दिया है। उन्होंने देश भर में मोर्चे के माध्यम से जाग्रति अभियान चलाने का भी सुझाव दिया।

बैठक में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय प्रभारी सांसद सुमित्रा महाजन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करूणा शुक्ला, राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती किरण घई, श्रीमती सुधा यादव सहित सभी प्रदेशों की अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री जयाबेन ठक्कर ने किया। ■

दीनदयालजी ने अपनी कर्मठता से राजनीति को प्रभावित किया

& ukukth ns'keq[k

nh नदयालजी स्वयं के संबंध में कभी चर्चा नहीं करते थे। उनके रहन–सहन एवं बातचीत की शैली इतनी सरल सहज और सादी थी कि उनमें समाई हुई महानता का आभास पाना कठिन था।

दीनदयालजी कहते थे– 'जो देश में, गांवों में इस समय अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उन लोगों की स्थिति बहुत खराब है। इस देश का भला तब तक नहीं होगा जब तक हम गांव के लोगों को शिक्षित संपन्न और योग्य नहीं बनाएंगे। भारत की विकास इसके बिना संभव नहीं । उनके पैर की बिवाइयां फट गईं हैं, उनको भरने की कोशिश नहीं करेंगे, उन्हें पर्याप्त वस्त्र नहीं हैं। उनके तन ढकने का इंतजाम करना होगा। उनके बच्चों को कुपोषण से बचाते हुए उन्हें पोषक आहार का प्रबंध करना होगा। उनमें से प्रत्येक को लाभदायी रोजगार उपलब्ध नहीं कराएंगे, उनके रहने की आवास की व्यवस्था नहीं होगी, उन्हें मानवीय सुविधा के अनुसार उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तब तक भारत का भला नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा कर पाए तो भारत का विकास होगा और भारत की आत्मा को शांति मिलेगी।'

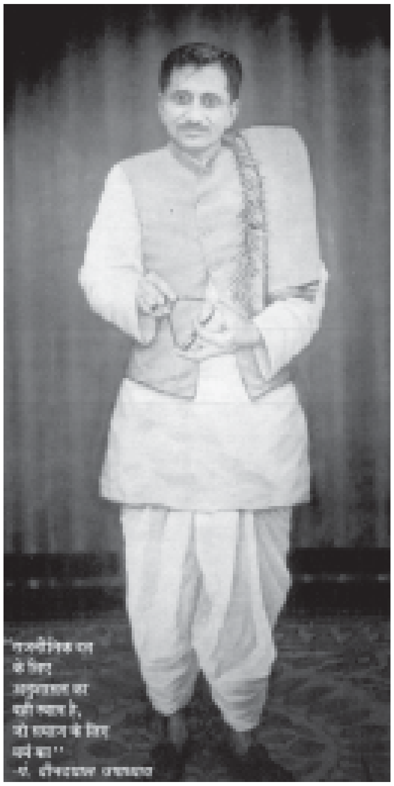

आजकल लोग प्रकाशन, विज्ञापन और भाषण में लग गए हैं। परन्तु धरती पर काम प्रारम्भ करने से कतराते हैं। जब तक धरती पर कार्य प्रारम्भ नहीं होगा तब तक कुछ भी संभव नहीं। नागरिक स्वालंबन की दिशा में हमें अपनी योजनाओं को ले जाना होगा। व्यक्ति–समाज की सोच में स्वालंबन के बिना स्वाभिमान नहीं जग सकता। अतः समाजोन्मुखी कार्य की प्राथमिकता को सरकार और समाज दोनों को समझना होगा। जब भी राष्ट्रोत्थान यानि समाज के शोषित पीड़ित दलित के उत्थान के प्रति हम ईमानदारी से कार्य करेंगे, उनकी समस्याओं को उनके ही सृजनशीलता से समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो कोई कारण नहीं है कि समाज हमारे पास खड़ा हो। आज अभाव यदि हो गया है तो सिर्फ कार्य और दायित्व के प्रति ईमानदारी का। पंडितजी राजनैतिक वातावरण से कभी प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने अपनी सरलता सहजता और कर्मठता से राजनीति को प्रभावित किया है। आजादी के 62 वर्षों के बाद भी हम दुर्दशा के दौर से गुजर रहे लोगों के आंसू पोंछने में समर्थ नहीं हैं। हमें अभाव से ग्रस्त लोगों में जागृति लानी होगी और पहल करना होगा। उनकी सृजन शक्ति काम में नहीं लाएंगे तब तक अभाव दूर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज करोड़ों लोगों की सृजनशीलता काम में नहीं आ रही है। जब तक मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, मेरी इच्छा नहीं होगी कोई मुझे कैसे पढ़ा सकता है। आप बढ़िया से बढ़िया किताब ले आएं, व्यवस्थाएं जुटा दें, यदि मुझे पढ़ना ही नहीं है तो इन सबसे क्या होगा।

पहले ऐसे लोगों के मनोवृत्ति का जागरण करना होगा। उनकी सृजनशीलता के द्वारा उन्हें स्वयं अपने आधार पर खड़ा करना होगा। स्वावलंबन मानव की पहली आवश्यकता है। क्या बिना स्वावलंबन के कोई स्वाभिमानी हो सकता। जिस समाज या जिस देश में स्वावलंबन नहीं उस देश को संसार में सम्मान नहीं मिल सकता। देश आजाद हुआ। हमें स्वाधीनता मिली। हमें हर गांव में स्वाधीनता का माहौल पैदा करना चाहिए था। हमें स्वतंत्रता इसलिए मिली कि हम स्वाधीन राष्ट्र के स्वाभिमानी नागरिक बनें। व्यक्ति, परिवार और आबादी के बारे में दीनदयालजी की यही आकांक्षा थी।

दीनदयालजी ने एकात्मता का सूत्र और अध्ययन करने के बाद 'एकात्ममानववाद' को देश के समक्ष रखा। एकात्मता का भाव रखने वालों को

गुटबाजी नहीं करनी चाहिए। राजनीति के माध्यम से समाज का परिवर्तन होगा या रचनात्मक कार्य के माध्यम से। यदि किसी को समझना हो तो उसे चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसे एक नमूने के रूप में जाकर देखना और समझना चाहिए।

बातें करने से समाज की समस्याओं का और पीड़ितों की पीड़ा दूर नहीं हो सकती। यह तो करने से ही होगा। एकदम परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि किसी ने ठान लिया तो कोई कठिन नहीं है। मुझे राजनीति के 28 वर्ष में जितना समाधान नहीं मिला उससे कहीं अधिक समाधान अब मिल रहा है। चित्रकूट में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है, वह 1991 से ही हुआ है। पांच सौ गांवों में मानव जीवन से संबंधित कोई कार्य ऐसा नहीं है जो इन गांवों में हो। तांगे के घोड़े के दोनों ओर चमड़े ही पट्टियां लगी रहती हैं। वह इसलिए कि घोड़ा सीधे रास्ते चले। हम भी संघ के ऐसे ही स्वयंसेवक हैं। मुझे दीनदयाल शोध संस्थान के अतिरिक्त कुछ भी दिखता नहीं। देश हमसे जो अपेक्षा करता है उसे पूरा करने में लगा रहता हूं।

दीनदयालजी एक सामान्य परिवार में जन्म पाकर भी असामान्य बन गए। परमपूज्य डा. हेडगेवारजी के स्वर्गवास के बाद 1940 में संघ कार्य प्रारम्भ करने मुझे और श्री जुनादे को आगरा भेजा गया था। उसी समय एम.ए. की शिक्षा प्राप्त करने स्व. दीनदयालजी भी वहां पहुंचे। एक कमरा किराए पर लेकर हम साथ रहने लगे। तब से लेकर उनके अंतिम समय तक कार्य की दृष्टि से हम साथ ही रहे हैं।

उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग ही नहीं जीवन का एक–एक क्षण प्रेरणास्पद रहा है। एक दिन प्रातः हम दोनों मिलकर सब्जी खरीदने बाजार गए। दो पैसे की सब्जी ली। लौटकर घर पहंचने को ही थे कि दीनदयालजी एकाएक रूक गए। उनका एक हाथ जेब में था, वे बोले ''नाना बड़ी गड़बड़ हो गयी! मैंने पूछा क्या गड़बड़ हो गयी? तो उन्होंने कहा कि मेरी जेब में चार पैसे थे उनमें से एक पैसा खोटा था। वह खोटा पैसा ही उस सब्जी वाली को दे आया हूं। मेरे जेब में बचे दोनों पैसे अच्छे हैं। वह क्या कह रही होगी। चलो उसे ठीक पैसा दे आएं।'' उनके चेहरे पर एक अपराधी जैसा भाव उतर आया था। हम दोनों वापस सब्जी वाली के पास पहुंचे। उसे वास्तविकता बताई तो कहने लगी, ''कौन ढूंढेगा तुम्हारा खोटा पैसा? जाओ जो दे दिया सो दे दिया।'' किंतु दीनदयालजी नहीं माने। उन्होंने उस बुढ़िया के पैसे के ढेर से अपना चिकना खोटा सिक्का ढूंढ निकाला। उसके बदले में अपनी जेब से दूसरा अच्छा पैसा बुढ़िया को दे दिया। तब कहीं जाकर उनके चेहरे पर संतोष का भाव उभरा। बुढ़िया की आंखें डबडबा गईं। वह कहने लगी, ''बेटा कितने अच्छे हो तुम। भगवान तुम्हारा भला करे।'' वे प्रेरणा के सागर थे।

हमने दीनदयालजी को सदैव काम करते देखा। हाथ में लिए काम को किसी ढंग से चलाए रखने मात्र से उन्हें संतोष नहीं होता था। यथास्थिति से उन्हें चिढ़ थी। हाथ में लिए कार्य की गहराई में जाना और व्यावहारिक आधार पर खड़ा करना उनका स्वभाव था। वे किसी व्यक्ति या विचारधारा के प्रति पूर्वाग्रह बनाकर चलने के विरूद्ध थे।

राजनीति में प्रवेश करने के बाद उनकी बुद्धि और कल्पना शक्ति केवल संगठनात्मक ढांचे या आए दिन उपस्थित होने वाले चुनावों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इन सभी कामों के साथ–साथ वे चिंतनशील वृत्ति की गहराई में उतरती गई।

वे किसी व्यक्ति या विचारधारा के प्रति पूर्वाग्रह बनाकर चलने के विरूद्ध थे। राजनीति में प्रवेश करने के बाद उनकी बुद्धि और कल्पना शक्ति केवल संगठनात्मक ढांचे या आए दिन उपस्थित होने वाले चुनावों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इन सभी कामों के साथ–साथ वे चिंतनशील वृत्ति की गहराई में उतरती गई।

दीनदयालजी एक सकारात्मक विचार करने वाले पुरूष थे। सकारात्मक मार्ग ढूंढना उनका स्वभाव था। बिरले लोग ही होते हैं, जो राजनीति में रहते हुए ''एकात्ममानववाद'' जैसे दर्शन को जग के सामने रख सकने में असमर्थ रहे हैं। दीनदयालजी कहा करते थे कि मानव मात्र के कल्याण का मार्ग तभी प्रशस्त हो सकता है जब उनका सर्वांगीण विकास हो। व्यक्ति एकांगी नहीं, बहुरंगी है। मानव तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का सम्मिलित रूप है।

आज कोई पसीना बहाना नहीं चाहता। गरीबों के सम्पर्क में रहना नहीं चाहता। उनकी सूखी रोटी की कोई स्वाद लेना नहीं चाहता, उनके गंदे बच्चों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता। सिर्फ बातें करवा लो। उन्होंने कहा कि हर काम सरकार से संभव नहीं हैं लेकिन जो लोग सरकार में हैं क्या उनके मन में यह भाव है कि सरकार यानि रचनात्मक कार्य। भारत में सरकार भी चलाना है तो उसे चलाने का भाव सदैव रचनात्मक होना चाहिए। रचनात्मक सरकार होगी तो समाज भी ऐसी सरकार के अनेक रचनात्मक कार्यों में स्वतः रूचि लेगी। रचनात्मक कार्य बिना, प्रत्येक नागरिक के सृजनशीलता का उपयोग किए बिना राष्ट्रदेवता को हम प्रसन्न नहीं रख सकते।

भारत बहुत बड़ा देश है। यहां जमीन कम, लोग अधिक हैं। अधिक लोगों को काम पर लगाने से ही देश का भला होगा।

आज यदि देश के प्रत्येक जिले में दीनदयाल शोध संस्थान जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संस्थान खड़े हो जाएं तो देश आर्थिक रूप से स्वतंत्र ही नहीं होगा बल्कि देश का स्वावलंबन बढ़ेगा और विश्व में हम स्वाभिमान से भारत माता का मस्तक ऊँचा कर सकने में सफल होंगे। जिस दिन ऐसा होना शुरू हो जाएगा तब हम पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी के इस कथन को कि ''समाज के अंतिम छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति का विकास ही मेरे देश के विकास का मानदंड होना चाहिए'' को हम सफल बना पाएंगे। ■

पाकिस्तान से हिन्दू परिवारों का पलायन चिंताजनक : राजनाथ सिंह

समाचार पत्रों में छपी यह रिपोर्ट अत्यंत चिंताजनक है, कि पाकिस्तान से हजारों हिन्दू परिवार तालिबान और उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर भारत और विशेषकर राजस्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। सूचनाओं के अनुसार विगत चार वर्षों में 5 हजार से अधिक पीड़ित हिन्दू परिवार सीमा पार कर भारत आ चुके हैं। वास्तविकता में स्थिति इससे अधिक नाजुक है और यह संख्या समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट से कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि विगत एक वर्ष से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का यह प्रचलन बढ़ा है।

केवल कुछ माह पूर्व स्वात घाटी में सिख समुदाय पर भी ऐसा ही अत्याचार हुआ था। पाकिस्तान में सभी अल्पसंख्यकों और विशेषकर हिन्दू और सिखों पर अत्याचार सामान्य सी बात होती जा रही है। भाजपा इस विषय पर अपनी चिंता व्यक्त करती है। यह तालिबान और उसके सहयोगियों द्वारा योजनाबद्ध जातीय उन्मूलन (Ethnic cleansing) का स्पष्ट

उदाहरण है। अल्पसंख्यकों के प्रति पाकिस्तान के पूर्ववर्ती रवैये को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान सरकार को इस उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता।

यह विडंबना है कि भारत सरकार जो हाल ही में शर्म–अल–शेख में संपन्न बैठक में पाकिस्तान के प्रति इतना नरम रवैया अपनाती है वही विगत वर्षों में हिन्दू और सिखों के अत्याचार को देख नहीं पाती।

भारत सरकार को अपनी वास्तविक जिम्मेदारी को समझना होगा न कि विदेश नीति की उन सूक्ष्म औपचारिकताओं में उलझना होगा जो कि इस प्रकार की बैठकों से संबंधित रहती हैं और पाकिस्तान के नेता कभी ठोस परिणाम नहीं देते। देश पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से मिले घावों के निराकरण के लिए एक ठोस परिणाम चाहता है।

भारत सरकार को इस विषय को पूरी ईमानदारी से उठाना चाहिए। केवल जबानी जमा खर्च या प्रतिकात्मक भाव–भंगिमा से कोई समाधान नहीं निकलेगा। एक प्रभावी प्रयास और कार्यवाही की तत्काल आवश्यकता है ताकि इन परिवारों, उनके अधिकारों और उनकी संपत्तियों की पूर्ण सुरक्षा पाकिस्तान सरकार द्वारा सुनिश्चित की जा सके।

भाजपा आशा करती है कि कम से कम अब तो प्रधानमंत्री और भारत सरकार इस वास्तविकता को स्वीकार करेंगे कि पाकिस्तान कभी भी मौखिक रूप से दिये गये अपने वायदों पर खरा नहीं उतरा है चाहे विषय आतंकवाद का हो, घुसपैठ का हो या मुंबई पर 26/11 के हमले का हो। अतः पाकिस्तान सरकार से कोई ठोस कदम सुनिश्चित कराने की आवश्यकता है। भारत इस प्रकार की तमाम घटनाओं के प्रति सदैव एक मूक–दर्शक बना नहीं रह सकता। ■

संप्रग सरकार ने लोगों की आशाओं पर पानी फेरा : प्रकाश जावडेकर

अपने पद पर 1926 दिन तक पदासीन रहने के बावजूद संप्रग सरकार ने लोगों की आशाओं पर पानी फेर दिया है तथा अपनी दूसरी पारी में 100 दिन के दौरान कुछ ठोस कार्य करने के वायदों को पूरा नहीं किया है। आम आदमी को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बारे में राहत देने के बजाय सरकार ने लोगों की परेशानियों को और अधिक बढ़ा दिया है। सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल के दाम तो बढ़ा दिए पर अपनी लापरवाही तथा भूल पर भूल करते हुए वह खाद्य पदार्थों के बढ़ते मूल्यों पर अंकुश नहीं लगा सकी। श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा चीनी के बढ़ते हुए मूल्यों के बारे में सरकार को भेजा गया पत्र घड़ियाली आंसू बहाना मात्र है। इस स्थिति में संप्रग सरकार – II के पहले 100 दिनों के प्रदर्शन को मूल्यवृद्धि के बारे में उसकी घोर और व्यापक विफलता ही माना जाएगा।

महिला आरक्षण बिल पेश करना, पिछड़ा क्षेत्र, अनुदान कोष को पुनर्संरचित करना, सूचना के अधिकार को मजबूती प्रदान करना, नरेगा और अन्य बहु–चर्चित कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाना, ई–गवर्नेंस तथा बैंकों और डाकघरों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना, मॉडल लोकसेवा विधि निर्मित करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिषद का गठन करना आदि कार्यक्रम केवल कागजों पर ही रह गए।

बिजली, इस्पात, खदान, सड़क तथा बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रम अपने लक्ष्यों से काफी पीछे चल रहे हैं। शिक्षा के अधिकार से संबंधित विधेयक यद्यपि पारित किया जा चुका है तो भी इसके क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण ब्यौरे अभी तक तय नहीं किए गए हैं।

संप्रग सरकार ने राष्ट्रीय सम्मति के मुद्दे तथा जयवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार संगठन और भारत–पाक समग्र वार्ता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी पूर्वकथित स्थिति से पूरी तरह पलटी मार ली है। पाकिस्तान में तनिक भी बदलाव नहीं आया है और वह सीमापार आतंकवाद पर अंकुश लगाने पर भी दिलचस्पी रखता प्रतीत नहीं हो रहा है। पाकिस्तान वार्ता–पटल पर बलूचिस्तान के मुद्दे को शामिल करने में सफल भी हो गया। यह सरकार द्वारा की गई भयंकरतम राजनयिक चूक है।■

आम आदमी निराश : किरण माहेश्वरी

Xत 29 अगस्त को जारी एक प्रेस वक्तव्य में भारतीय जनता महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक राजसमंद श्रीमती किरण माहेश्वरी ने कहा कि प्रथम सौ दिनों में संप्रग सरकार की कार्यपद्धति से आम आदमी निराश एवं हताश है। केन्द्र में नई सरकार गठित करते समय 100 दिनों के लिए बड़ी–बड़ी बातें की गईं। देश का कायाकल्प होने का सपना दिखाया गया। किन्तु बढ़ती महंगाई एवं भ्रष्टाचार ने आम आदमी की कमर ही तोड़ दी है।

महिला आरक्षण

विधायिका में महिला आरक्षण का वादा सरकार ने अपनी 100 दिवसीय कार्ययोजना में किया था। किन्तु इस दिशा में प्रगति शून्य है।

केन्द्रीय नियुक्तियों में महिला प्रतिनिधित्व

संप्रग सरकार ने नियुक्तियों में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने का भी वादा किया था। इन 100 दिनों में इसके लिए नाम मात्र के भी प्रयत्न नहीं किए गए। कथनी एवं करनी में अंतर कांग्रेस की सनातन परम्परा है।

महिला आरक्षण सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय अभियान

सरकार ने वादा किया था कि वे महिला सशक्तिकरण को गति देने के लिए विशेष राष्ट्रीय अभियान संस्थापित करेंगे। यह अभियान महिला उन्नयन के लिए राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर नीति निर्धारण, संसाधनों की उपलब्धता एवं सर्वेक्षण का कार्य करेगा। इस अभियान की सरकार में कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसे पूरी तरह से भुला दिया गया है।

महंगाई

भाजपा महिला मोर्चा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि पर चिंता व्यक्त करता है। 80 रूपए किलो में दालें, 70 से 90 रूपए किलो खाद्य तेल, 300 रूपए किलो घी, 28 रूपए किलो शक्कर, 20 रूपए किलो गेहूं, 25 से 80 रूपए किलो चावल के भावों पर आम आदमी जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम आवश्यक पोषक तत्व भी नहीं ले पा रहा है। केन्द्र सरकार मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के कोई प्रयास ही नहीं कर रही है। वे शून्य मुद्रास्फीति की बातों से देश को भ्रमित कर रहे हैं। मूल्य वृद्धि का सबसे अधिक दुष्प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। देश आवश्यक वस्तुओं की कमी झेल रहा है किन्तु केन्द्र सरकार सो रही है।

खाद्य सुरक्षा

सरकार ने देश के प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम पोषण हेतु अनाज मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाने एवं बहुसूचना पत्रक उपलब्ध करवाने का वादा किया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम को बनाने की केवल बातें की गई किन्तु इसे बनाने के कोई प्रयास नहीं हुए।

सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पत्रक

सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा एवं अन्य सामाजिक लाभों एवं जीवन वृत्ति भुगतान बैंक एवं डाकबचत खातों द्वारा करवाने की घोषणा की थी। इसे भी व्यवहारिक धरातल पर लाने के कोई प्रयास नही किया गया।

ग्रामीण रोजगार में पारदर्शिता

ग्रामीण रोजगार में पादर्शिता के लिए जिला स्तर पर लोकायुक्त से जांच व्यवस्था भी सरकार का एक वादा था। इसे भी सरकार ने भुला दिया है। ■

दाल, चावल, चीनी सब महंगे : नंदकिशोर गर्ग

1 सितम्बर को भाजपा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. नन्द किशोर गर्ग ने आज एक वक्तव्य में कहा है कि मनमोहन सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं किन्तु सरकार ने उन वायदों को पूरा नहीं किया जिनको अगले 100 दिनों में पूरे करने की घोषणा की थी। स्वयं कांग्रेस ने राष्ट्रपति अभिभाषण के माध्यम से भी इस प्रकार के वायदे किए थे किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इन 100 दिनों में आम आदमी के हितों की वकालत करने वाली कांग्रेस सरकार के राज में सबसे ज्यादा परेशान आम आदमी ही हुआ है। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी की जेब में कुछ भी नहीं बचता। दाल से लेकर चावल, चीनी के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। यह भी तब जबकि सरकारी गोदामों में अनाज भरे पड़े हैं। क्या इसका यह अर्थ नहीं कि खाद्य मोर्चे पर सरकार पूरी तरह विफल हो गई है? कृषि मंत्री को भी इस बात की जानकारी थी कि चीनी का उत्पादन इस वर्ष कम हुआ है और दाल का उत्पादन भी पिछले वर्ष कम हुआ था किन्तु उन्होंने इन वस्तुओं के आयात के लिए कोई प्रयास नहीं किया। यदि इन वस्तुओं की आयात करके बाजार में उतारा जाता तो कीमतें आसमान को नहीं छूती।

प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस को जनता ने अपना जनादेश शासन चलाने और समस्याओं के निपटारे के लिए दिया था। यह कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वह सरकार को इस प्रकार चलाए जिससे आम आदमी को यह महसूस नहीं हो कि उसके साथ धोखा हुआ है। विदेश नीति के मामले में भी सरकार असफल रही है। पड़ौसियों से सम्बन्ध में कोई सुधार नहीं हुआ है। यहां तक कि ब्लूचिस्तान मुद्दे पर सरकार को शर्मसार होना पड़ा। भाजपा नेता ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि जिस सरकार का प्रधानमंत्री स्वयं अर्थशास्त्री हो उसके शासन में भी आवश्यक वस्तुएं आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं।

कांग्रेस यह भी बहाना नहीं बना सकती कि उसके सहयोगी दल उसका साथ नहीं दे रहे हैं। डॉ. गर्ग ने अंत में कहा कि जनता अब यह महसूस करने लगी है कि कांग्रेस आम आदमी की समस्याओं को सुलझाने के लिए गम्भीर नहीं है। सही मौके पर वह कांग्रेस को सबक सिखाने में देर नहीं करेगी। ■

वैश्वीकरण की दिशा एवं दशा

&Mk- lat; ikloku

विश्व को भारत ने ही वसुधैवकुटुम्बकम का नारा दिया एवं महाभारत में श्री कृष्ण ने ''सबै भूमि गोपाल की'' के गगनभेदी नारों से उस काल के लोगों को एक संदेश दिया था। यह अपने आप में हमारे स्थापित वर्चस्व एवं श्रेष्ठता का द्योतक था। भारत सोने की चिड़िया थी, और हम विश्व व्यापार में अग्रणी थे। मगर बीच के कालखण्ड के दौरान मुगलों एवं फिर अंग्रेजों के शासनकाल एवं उनकी स्वार्थपरक पद्धति के परिणामस्वरूप हमारी इन मान्यताओं एवं इन संस्थाओं को काफी आघात पहुंचा एवं हमारे प्राचीन मूल्य छिन्न भिन्न हो गए।

आजादी मिलने के पश्चात भी तत्कालीन सरकारों ने अर्थव्यवस्था का एक विशेष प्रारूप स्वीकार कर, उसका अंधानुकरण शुरू किया, जिस कारण से भी हमारे वैशिष्टय की रही सही चमक क्षीण हो गई। गैट एवं डब्ल्यूटीओ के निर्माण के बाद से विकासशील देश एवं विकसित देशों के बीच सम्बंधों में खटास बढ़ने लगी। 1991 की नई आर्थिक नीति के प्रावधानों के तहत उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया की धीमी शुरूआत हुई। उन दिनों राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों से इस परिप्रेक्ष्य में काफी आशंकाएं व्यक्त की गई एवं सरकार भी काफी सशंकित दिखी। 1991 से 1998 के काल में अपने देश में काफी राजनैतिक उथल–पुथल रही, जिस कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया दृश्यमान नहीं हो सकी। मगर 1998 के बाद से अब तक जो आंकड़े एवं तथ्य सामने आए हैं उनसे यदि काफी कुछ उम्मीदें नहीं हैं तो वे हतोत्साही भी नहीं है। विशेषकर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हम लोगों ने अब तक पिछले वर्ष (2001–2002) में 36,500 करोड़ का निर्यात करोबार किया एवं यह वृद्धि पिछले दशक से 100 गुना ज्यादा है। हमारे दो लाख से अधिक कामगार विकसित देशों में साफ्टवेयर के कामों में कार्यरत हैं एवं देश में इससे जुड़े उद्योगों में लगभग 10 लाख लोग कार्यरत हैं। आज सम्पूर्ण दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है मगर हमारी अर्थव्यवस्था इससे अछूती है। हमारा देश दुनिया का दूसरा शक्तिशाली सशक्त एवं जीवंत अर्थव्यवस्था वाला देश है। हमारी विकास दर पिछले विकास दरों से काफी ज्यादा है एवं 2008 तक हमारा देश वर्तमान विकास दर की गति से बढ़ते हुए साफ्टवेयर के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।

> ***एक समय था जब हमारे देश के बड़े–बड़े उद्योगपतियों ने उदारीकरण की नीतियों का स्वागत किया था पर आज उन्हीं में से कुछ लोग उसे अपना संकट बता रहे हैं। हमें यह देखना होगा कि हमारे देश के औद्योगिक एंव व्यावसायिक घराने, शिल्पकारों के घराने तथा ऐसे ही प्राचीन घराने जो कभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था के मेरूदण्ड हुआ करते थे, संकट से ना घिरें। ऐसे प्रयास सरकार से न सिर्फ अपेक्षित बल्कि लाजिमी भी हैं।***

आज हमारे पास अनाज का पर्याप्त भण्डार है, प्रर्याप्त विदेशी मुद्रा है, मुद्रा स्फीति नियंत्रण में है, स्थिर सरकार है एवं ठोस निर्णय करने की क्षमता भी है। हमारा देश आज गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। हम चावल निर्यात में दूसरे स्थान पर हैं एवं दूध, चीनी, रूई का भी निर्यात कर रहे हैं।

इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने में वैश्वीकरण के कारण विद्यमान प्रावधानों से पूरा लाभ तो नहीं मगर अंशतः लाभ अवश्य मिला है, जिसे हमें स्वीकारना चाहिए। सम्पूर्ण दुनिया के उद्योगपतियों एवं व्यवसाइयों की रूचि भारत में बढ़ी है, जिसमें प्रमुख रूप से जी.ई. कम्पनी के अध्यक्ष जैकवैल, इनटेल के अध्यक्ष केग्रे वैरेट, बिल गैट्स, डॉ. इरविन जैकब, जॉन डेल एवं अभी–अभी रूस के राष्ट्रपति पूतिन तथा और बड़े–बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष या तो भारत आ रहे हैं या भारत सरकार के मंत्री को अपने यहां निमंत्रण दे कर बुला रहे हैं। अनेकानेक निवेशकर्ता लगातार भारतीय औद्योगिक क्षेत्र एवं सरकार के सम्पर्क में हैं, जिससे भारत के दुनिया के पटल पर एक सार्थक एवं सबल हिस्सेदारी होने की गुंजाइश है।

आज हमारे स्वदेशी उद्योग पर खतरा मंडरा रहा है। कम्प्यूटरीकरण के कारण रोजगार के अवसर में गिरावट आयी है। कृषि के क्षेत्र में भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने से किसानों के मन में कुछ सहज आशंकाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। वैश्वीकरण के बाद से भारत के प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों में बदलाव अवश्यंभावी था मगर तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) में हमने काफी शानदानर ऊंचाइयों को छुआ है। परन्तु हमें यह भी दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए कि इस दौर में तेजी से एक जुगाड़ी एवं तिकड़मी वर्ग जैसे मध्यस्थ खड़े हो गए जिनके कारण अरबों की राशि की गफलतबाजी हुई। यह स्थिति विशेषकर वित्तीय क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखने को मिली। वर्तमान सरकार ने उस पर भी अपने नियामक अभिकरणों के द्वारा एक ईमानदार पहलकदमी किया है जिसकी सराहना होनी चाहिए।

एक समय था जब हमारे देश के

बड़े–बड़े उद्योगपतियों ने उदारीकरण की नीतियों का स्वागत किया था पर आज उन्हीं में से कुछ लोग उसे अपना संकट बता रहे हैं। हमें यह देखना होगा कि हमारे देश के औद्योगिक एंव व्यावसायिक घराने, शिल्पकारों के घराने तथा ऐसे ही प्राचीन घराने जो कभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था के मेरूदण्ड हुआ करते थे, संकट से ना घिरें। ऐसे प्रयास सरकार से न सिर्फ अपेक्षित बल्कि लाजिमी भी हैं।

अपना देश उद्यमी प्रधान रहा है, उपभोक्ता प्रधान कभी नहीं रहा। दुनिया के विकसित देश हमें एक बड़े बाजार के रूप में देखना बंद करें। हमारे देश में स्वरोजगार की परंपरा प्राचीनकाल से रही है। अतः हम अपने यहां पब्लिक सेक्टर एंव प्राइवेट सेक्टर की बजाय पीपुल सेक्टर को बढ़ावा देना चाहेंगे। अनौपचारिक क्षेत्रों में रोजगार का सृजन अधिकाधिक हो। इसकी असीम संभावनाएं मौजूद हैं। इन क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन का अन्वेषण किया जाना चाहिए। सरकारी कोषों का दुरूपयोग होने से बचाने का प्रयास सख्ती से होना चाहिए। अन्य प्रकार के अंकेक्षण के साथ–साथ सोशल आडिट, इनर्जी आडिट एवं डिजिटल आडिट भी हो ऐसा प्रयास करके गैर आवश्यक खर्चों पर रोक लगाया जा सकता है एवं उस बची हुई राशि से हम समाज के अन्य क्षेत्रों की जवाबदेही एवं जिम्मेदारी औचित्यपूर्ण ढंग से निभा सकते हैं। देश के सभी बड़े–बड़े कॉरपोरेट क्षेत्रों के हेतु कारपोरेट सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility) के अनुच्छेद को अनिवार्य करके हम उन्हें भी समाज एवं देश के निर्माण में ठीक ढंग से लगा सकते हैं।

हमारा यह प्रयास हो कि देश का कोई भी व्यक्ति, समाज, क्षेत्र, किसी मामले में वंचित न रहे। किसी अन्य देश की ललचाई निगाह हमारी ओर है तो हम उससे सख्ती से निपटें। इस सरकार से हम यह अपेक्षा करते हैं कि देश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो तीन प्रमुख संवैधानिक संस्थान बनाई गई हैं, उन्हें, सशक्त रूप से कारगर बनाने का प्रयास ईमानदारीपूर्वक हो। प्रथमतः नागरिक सुरक्षा हेतु जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग बना है, वह केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहे बल्कि आयोग यह सुनिश्चित करे कि न्याय से वंचित कितने इस समाज के लोगों को राहत दिलाई जा सकी है। उस पर एक सम्पूर्ण श्वेत पत्र जारी हो। साथ ही सथ हम यह भी मांग करते हैं कि इस संवैधानिक संस्था को अधिकाधिक अधिकारों से लैस किया जाए। द्वितीय, इन वर्गों के आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से बनाए गए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सहायता से इस समाज में कितने उद्यमी खड़े किए गए हैं?

क्या वे प्रर्याप्त हैं अथवा केवल खानापूर्ति की गई है? तृतीय, अम्बेडकर फाउंडेशन, जो समाज के शैक्षणिक स्तर को उत्कृष्ट करने के लिए बनाया गया है क्या वह फाउंडेशन उचित कार्य कर रहा अथवा नहीं? इन सब पर विषद् चर्चा हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। क्या आज इस वैश्वीकरण के दौर में देश की सामाजिक नीति को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है? ऐसी सोच भी आगे बढ़नी चाहिए। दुनिया के अन्य देश अपने यहां के वंचितों के लिए कौन–कौन से प्रयास किस ढंग से कर रहे हैं? इस पर भी एक अन्वेषण होना चाहिए जिससे भारत के वंचितों की दशा में अपेक्षित सुधार हो सके। वंचितों एवं गरीबों के लिए जो विशेष अंगीभूत योजना है उस संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों से उत्साहवर्धक परिणाम क्यों नहीं आ सके? यह भी खोज का विषय है! यह वंचित समाज सरकार के समक्ष यह मांग रखता है कि इनके सभी पहलुओं का अध्ययन करके इन वर्गों के लिए नए सिरे से एक कार्ययोजना बने। ■

गुजरात महिला मोर्चा

महंगाई के विरोध में प्रदर्शन

भाजपा महिला मोर्चा बड़ोदा (गुजरात) की महिला कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार के अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों के कारण बेलगाम बढ़ती महंगाई के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंका। यह प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती जयाबेन ठक्कर के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

प्रदर्शन से पूर्व जनसभा को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री जयाबेन ने कहा कि केन्द्र में सत्ता में बैठी यूपीए सरकार की नीतियां जनविरोधी हैं यूपीए सरकार के केन्द्र में सौ दिन पूरे होने को हैं। पूरा देश महंगाई और सूखे की चपेट में हैं। इन सौ दिनों में केन्द्र सरकार इन समस्याओं से निपटने में असफल साबित हुई है। उन्होंने मांग की कि यह सरकार समस्याओं का समाधान करे या सत्ता छोड़ दे। ■

भाजपा विधायकों ने सौंपे इस्तीफे

jk ज्य की सत्ता को अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का शासन करार देते हुए भाजपा विधायकों ने 09 सितम्बर को अपना सामूहिक इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। साथ ही 11 अक्टूबर को राजभवन घेराव का एलान किया।

इससे पहले विधायकों ने राज्यपाल के. शंकरनारायणन से भी मुलाकात की और उन्हें दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से यहां सत्ता चला रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन में प्रदेश के साथ जो प्रयोग हुआ है, वह लोकतंत्र से खिलवाड़ है। राज्यपाल पद की मर्यादा के अनुरुप तत्काल विधानसभा भंग करने की अनुशंसा करें। भाजपा के सभी विधायक, प्रदेश पदाधिकारी व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से मोरहाबादी मैदान पहुंचे, जहां महात्मा गांधी और फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सूबे में अराजकता बर्दाश्त नहीं करने का संकल्प लिया। वहां से काफिला प्रोजेक्ट भवन सचिवालय पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष रघुवर दास ने उन्हें बताया कि 19 जनवरी 2009 से सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, चुनाव छह माह में होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं कर राष्ट्रपति शासन की अवधि 19 जनवरी 2010 तक कर दिया गया। केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने संसद में कहा था कि यहां मानसून के बाद चुनाव कराए जाएंगे। यूपीए की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इसकी पक्षधर थीं। बावजूद इसके विधानसभा को भंग न कर निलंबित रख कांग्रेस ने छलने का काम किया है। यहां से भाजपा विधायकों व नेताओं का काफिला विधानसभा पहुंचा और अध्यक्ष आलमगीर आलम को इस्तीफा सौंपते हुए इसे आज ही स्वीकार किया जाए और इसकी सूचना चुनाव आयोग को देने की मांग की।

इस्तीफे के समय भाजपा के 21 विधायक उपस्थित थे। इनमें मनोनीत विधायक जेपी गालस्टीन भी थे। जबकि सरयू राय का इस्तीफा पार्टी की ओर से दिए जाने की बात कही गई। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता व सांसद यशवंत सिन्हा, अर्जुन मुंडा, सुदर्शन भगत, उप नेता डा. दिनेश षाडंगी, सीपी सिंह, सत्यानंद भोक्ता, डा. सूर्यमणि सिंह, गणेश मिश्र, संजय सेठ, बीसी विद्यार्थी, प्रदीप सिन्हा समेत अन्य कई नेता उपस्थित थे। भाजपा के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा में विधायकों की संख्या अब 42 रह गई है।

ज्ञात हो कि महाराष्ट्र व हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव के घोषणा के समय ही यह आशा की जा रही थी कि झारखण्ड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। क्योंकि झारखण्ड में गत लगभग 9 माह से राष्ट्रपति शासन लागू है। जिससे स्थानीय जनों में भी काफी आक्रोश है।

राज्य में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के न होने के कारण इस नवनिर्मित राज्य का विकास मानो ठप्प हो गया है। फिर जिस तरह से पिछले दिनों कांग्रेस के इशारे पर राज्य में राजनैतिक अस्थिरता का वातावरण पैदा किया गया। उससे कांग्रेस के प्रति असंतोष का वातावरण है। जिसे कांग्रेस नेतृत्व जानती है और वह राज्य में विधानसभा चुनाव करान से कतरा रही है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड में तुरन्त विधानसभा चुनाव कराने की मांग करती रही है। ■

त्रिशंकु विधानसभा बनने के आसार

gरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है राज्य के इतिहास पर नजर डाली जाए तो अब हुए 10 विधानसभा चुनावों में छह बार कांग्रेस एवं चार बार अन्य दल सरकार बनाने में कामयाब रहे। इन दलों में जनता पार्टी, लोकदल, भाजपा–हविपा व इनेलो शामिल हैं। जनता पार्टी के नाम अब तक की सर्वाधिक 75 सीट जीतने का रिकॉर्ड है।

हरियाणा में 13 अक्टूबर को मतदान होना है और 22 अक्टूबर को मतगणना होगी। मतदाता पहचान पत्र का काम 99 प्रतिशत पूरा हो चुका है। जिन मतदाताओं का पहचान पत्र नहीं बना है वह चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए पहचान पत्र ले जाकर मतदान कर सकेगा। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या एक करोड़ 20 लाख 87 हजार 743 है, इसमें 10 लाख 59 हजार 711 नए मतदाता शामिल होने का अनुमान है। इसके बाद मतदाताओं की कुल अंतिम संख्या एक करोड़ 31 लाख 47 हजार 454 हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दस में से नौ सीटें मिली थीं और चुनाव परिणामों से उत्साहित कांग्रेस ने निर्धारित समय से पहले (छह माह पहले) विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की।

हरियाणा राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने का फैसला सर्वसम्मति से किया गया। मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद राज्यपाल जगन्नाथ पहाडिया ने राज्य विधानसभा को भंग कर दिया।

हरियाणा में इस बार सत्ताधारी दल कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), हरियाणा जनहित कांग्रेस (हजकां) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) गठबंधन तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) से नाता तोड़कर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हरियाणा इकाई के भाजपा नेताओं ने पिछले वर्ष इनेलो के साथ गठजोड़ का विरोध किया था। वर्ष 2004 में दोनों पार्टियां अलग–अलग चुनाव लड़ चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हजकां व बसपा ने हाथ मिला लिया। सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस (एचजेसी) और बीएसपी ने भी एक दूसरे से हाथ छुड़ा लिया। बसपा और हजकां ने अब अकेले दम पर राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत पार्टी के मौजूदा कुछ विधायक बन सकते हैं, जिनकी छवि क्षेत्र में अच्छी नहीं है।

विधायक केंद्रित–एंटी इंन्कबेंसी का फैक्टर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। परिसीमन के कारण विधानसभा क्षेत्रों का बदला राजनीतिक परिदृश्य भी नए समीकरण बना सकता है।

हरियाणा में सत्तारूढ़ कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनावों में प्रचार के दौरान विकास के मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुडा सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे है।

कांग्रेस सरकार जनता के पैसे से अख़बारों और टीवी में हरियाणा के नंबर–1 होने का जश्न मना रही है। विपक्षी इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) और भाजपा गठबंधन भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद और बदतर होती कानून एवं व्यवस्था को मुद्दा बना रहे हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। केन्द्र की

आंकड़े

हरियाणा विधानसभा में कुल सीटें	:	90
सरकार बनाने के लिए चाहिए	:	46
विपक्ष की भूमिका के लिए चाहिए	:	10

लोकसभा में – कांग्रेस 9, हजकां–1
राज्यसभा में : कांग्रेस 3 और इनेलो 2

foèkku lHkk pquko ifj.kke 2005

कांग्रेस	:	67
इनेलो	:	9
भाजपा	:	2
अन्य	:	12

o"k	çe[k ny	jujvi
1967	कांग्रेस 48	भारतीय जनसंघ 12
1968	कांग्रेस 48	विशाल हरियाणा पार्टी 16
1972	कांग्रेस 52	कांग्रेसएस 12
1977	जनता पार्टी 75	कांग्रेस 3
1982	कांग्रेस–निर्दलीय 36.16	लोकदल 31
1987	लोकदल–भाजपा 60.17	कांग्रेस 5
1991	कांग्रेस 51	जनता पार्टी 16
1996	हविपा–भाजपा 33.11	समता 24
2000	इनेलो 47	कांग्रेस 21
2005	कांग्रेस 67	इनेलो 9

यूपीए सरकार व राज्य सरकार ने जो काम किए हैं, उससे जनता खुश है इसलिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इतिहास रचेगी।

भाजपा ने राज्य सरकार की ओर से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की आशंका जतायी है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। भाजपा ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती के अलावा बैनर और पर्चे से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की तस्वीरें हटाने की मांग की। शुक्र हो, चुनाव आयोग का, जिसने समय रहते चुनाव आचार संहिता लागू कर बाबू लोगों के हाथ–पैर बांध दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कार्यवाहक होकर भी सरकारी धन के जरिये अपनी सरकार और पार्टी के लिए तर्कहीन तरीक़े से प्रचार किया... और, यह सब तब हो रहा था, जब प्रदेश का आधा हिस्सा सूखे से जूझ रहा था।

हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में किसान सूखे की मार से इस कदर परेशान हैं कि बहुत–सी जगहों पर किसानों ने अपनी धान की फसल को न बचा पाने की सूरत में उस पर ट्रैक्टर फेर दिए। किसानों की इस व्यथा पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। अक्सर हुड्डा पर आरोप लगते रहे हैं कि वह रोहतक के मुख्यमंत्री ज्यादा हैं, हरियाणा के कम। क्योंकि ज्यादा विकास रोहतक के आस–पास के इलाके में ही हुआ है, और हरियाणा के बाकी हिस्सों पर अपहरणकर्ता काबिज़ रहे हैं। दिनदहाडे लूट और मार–पीट की घटनाओं से परेशान हो, यहां कोई अच्छा अफसर पोस्टिंग नहीं लेना चाहता। उधर, इनेलो नेता ओमप्रकाश चौटाला ने तो वादों की पोटली खोल दी है। बिजली मुफ्त... पानी मुफ्त... सारे कर्ज़े माफ... बेरोज़गारी भत्ता बढ़ा दिया. .. लड़कियों को स्कूटर पर भी चढ़ा दिया... महिलाओं को गैस कनेक्शन और चूल्हे मुफ्त... फिर काम करने की ज़रूरत कहां रह गई...? गुड़गांव व फरीदाबाद में औने पौने दाम पर 48 औद्योगिक प्लॉट और सोनीपत में एजूकेशन सिटी के लिए जमीन आवंटित किए जाने से सरकार को करोड़ों का चूना लगा है। प्लॉट आवंटित करने के बजाए नीलामी में बेचे जाने चाहिए थे। इन प्लॉटों के आवंटन से हुड्डा का चरित्र, चाल व चेहरा बेनकाब हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा अपनी घोषणाओं को लागू करवाने के प्रति गंभीर नहीं रही। उन्होंने हर वर्ग के साथ धोखा किया है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को ज्यों का त्यों लागू नहीं किया गया। इससे सरकारी कर्मचारियों में गुस्सा है। साढ़े चार साल में आम आदमी को हुड्डा सरकार ने कोई प्लॉट नहीं दिए, लेकिन विधायकों सांसदों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद रातों रात दो करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के प्लॉट 28–28 लाख रुपए में बांट दिए गए। चुनाव के दौरान राज्य की जनता मुख्यमंत्री से जवाब मांगेगी।

पिछले दिनों भाजपा के हरियाणा मामलों के प्रभारी विजय गोयल ने सह प्रभारी हरजीत सिंह ग्रेवाल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कृष्णपाल गुज्जर की मौजूदगी में इनेलो से नाता तोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, भाजपा लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कटु अनुभव के बावजूद इनेलो के साथ समझौते को आगे बढ़ाने के पक्ष में थी। लेकिन इनेलो ने बदली हुई परिस्थितियों को नजरअंदाज किया और जमीनी हकीकत को भांपने की कोशिश नहीं की। पहले के मुकाबले पार्टी के मजबूत होने का जिक्र करते हुए गोयल ने कहा, भाजपा अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है और पार्टी सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी।

विधानसभा भंग किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, अगर हरियाणा में समय से पहले चुनाव कराने थे तो लोकससभा के साथ ही होने चाहिए थे ताकि करोड़ों रुपए का खर्च बच जाता। उन्होंने हुड्डा सरकार की ओर से जारी किए जा रहे विज्ञापनों को आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष .ष्ण पाल गूजर ने किसी से तालमेल की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। चुनाव के बाद भाजपा का समर्थन हासिल करने के चौटाला के बयान पर गुर्जर ने कहा, अब ऐसी कोई संभावना नहीं बची है। ■

प्रमुख तथ्य :

- हरियाणा के करीब 43 वर्ष के इतिहास में वर्ष 82 और 96 के चुनाव को छोड़कर हर बार कोई न काई दल पूर्ण बहुमत लेकर आया।
- आठ बार चुनाव में किसी ने किसी दल को पूर्ण बहुमत मिलता ही रहा है।
- जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वर्ष 77, 87 और 96 के चुनाव में विकट हालात से गुजरना पड़ा। 1977 में मात्र 3 और 87 में 5 जबकि 96 में 9 सीटों से संतोष करना पड़ा।
- कांग्रेस का अब तक का रिकॉर्ड 67 सीट जीतने का रहा है।
- राज्य में वर्ष 77, 87, 2005 के चुनाव में विपक्ष नहीं रहा। दो चुनाव में कांग्रेस को एवं एक चुनाव में इनेलो को कम सीटों के कारण विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका नहीं मिला। उनके दल से किसी नेता को यह सम्मान नहीं दिया गया।
- वर्ष 1982 के बाद भाजपा राज्य में तीन बार सत्ता में भागीदार हो चुकी है। 1982 में भाजपा ने प्रदेश में पहला चुनाव लड़ा था। तब से लेकर आज तक अकेले दम पर कमल नहीं खिल सका। 1987, 1996 और 2000 में यह सत्ता में भागीदार रही।

मध्यप्रदेश में हर वर्ष एक लाख युवकों को रोजगार मिलेगा : शिवराज सिंह चौहान

Xत 6 सितम्बर, 09 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोहद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित युवा मोर्चा युवा नवमतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जब देश में कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियों के कारण पिछले तीन माह में 5 लाख लोग अपनी आजीविका से हाथ धो चुके हैं। मध्यप्रदेश में रोजगार सृजन की महत्वाकांक्षी योजना पर अमल किया जा रहा है। हर वर्ष एक लाख युवकों को रोजगार देने का हमारा संकल्प है। इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर, नए उद्यम और उद्योग खोले जा रहे हैं।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी पहली शर्त यही होती है कि मध्यप्रदेश के युवक रोजगार के लिए भटकते न रहें और प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में आंचलिक युवकों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए मध्यप्रदेश में हर जिले में पालीटेक्निक और आईटीआई खोले जा रहे हैं। इससे प्रशिक्षित युवक तैयार हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हर गरीब और प्रतिभाशाली छात्र के लिए छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम गरीबों में भेदभाव करने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। पांच वर्ष की उपलब्धियां इसका सबूत हैं। गोहद विधानसभा उपचुनाव आंचलिक जनता के लिए एक अवसर है। वह भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सोबरन जाटव को विजयी बनाकर मुख्यमंत्री और पार्टी के हाथ मजबूत करे।

उन्होंने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे भाजपा सरकार की जनोन्मुखी नीतियां जन–जन तक पहुंचाएं और 10 सितंबर को होने वाले मतदान में पार्टी प्रत्याशी सोबरन जाटव को विजयी बनाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री प्रभात झा, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वास सारंग सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। आपने कसमागुर्जर, खराउना, आरोली, पिपरसान और इटायदा में सघन जनसंपर्क किया। श्री शिवराज सिंह चौहान ने युवकों को याद दिलाया कि क्रांति युवा ऊर्जा ही ला सकती है। पार्टी के युवा नवमतदाताओं को इस उपचुनाव में अपनी कर्मठता और लगन का परिचय देना है। वे 10 सितंबर को घर–घर पहुंचें और अधिकतम मतदान पार्टी प्रत्याशी सोबरन जाटव के समर्थन में कराए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें आप समर्थन दें, भिंड जिले और गोहद क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी शिवराजसिंह के कंधे पर होगी। उन्होंने कहा कि गोहद क्षेत्र की जनता सोबरन सिंह जाटव को अपने मत से विधायक चुनेंगी। लेकिन उसे दोहरा फायदा यह होगा कि गोहद क्षेत्र के दूसरे विधायक के रूप में मुख्यमंत्री निवास के द्वार उनके लिए हमेशा खुले मिलेंगे। मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार ने बच्चों की पढ़ाई, रोजगार, क्षेत्रीय विकास, किसानों को भरपूर राहत, मजदूरों को सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा देने का काम किया है, जो धरातल पर दिखाई देता है। उपलब्धियों

जब देश में कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियों के कारण पिछले तीन माह में 5 लाख लोग अपनी आजीविका से हाथ धो चुके हैं। मध्यप्रदेश में रोजगार सृजन की महत्वाकांक्षी योजना पर अमल किया जा रहा है। हर वर्ष एक लाख युवकों को रोजगार देने का हमारा संकल्प है। इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर, नए उद्यम और उद्योग खोले जा रहे हैं।

के आधार पर ही आपको भाजपा प्रत्याशी का समर्थन करना है। श्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर गोहद के विशाल मैदान में आयोजित नवमतदाता सम्मेलन में शामिल हजारों युवकों और गोहद क्षेत्र के महिला, पुरुष मतदाताओं ने मुट्ठियां तानकर भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प घोषित किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर पैदा होने वाली हर कन्या ससुराल जाते समय लखपति बनकर ससुराल जाएगी। यह करिश्मा मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना इसका सबूत है और देश भर में भाजपा सरकार की योजनाओं की सराहना की जा रही है। उन्होंने मतदाता भाईयों से अपील की कि वे विकास के नाम पर क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए भाजपा को विजयी बनाए। कांग्रेस हर मामले में विफल साबित हुई है। आजादी के बाद कांग्रेस ने नारे, वायदे दिये हैं। लेकिन प्रगति, विकास, का विकेन्द्रीकरण नहीं किया। यही कारण है कि अमर्त्य सेन को कहना पड़ा कि देश की तीन चौथायी जनता को 20 रु. दिन में गुजारा करना पड़ता है।

देश के प्रति व्यक्ति आय घटी है। लेकिन मध्यप्रदेश में बढ़ी है। सकल घरेलू उत्पाद में भी पांच वर्षों में मध्यप्रदेश राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। देश में पांच वर्षों में जो दुर्दशा हुई है, वह जन–जन के लिए महंगायी का दंश बनी है। यह चुनाव ऐसा अवसर है कि मतदाता उपलिब्धयों के लिए भाजपा को पुरुस्कृत करेंगे और विफलता के लिए कांग्रेस को दंडित करेंगे। इससे गोहद ही नहीं मध्यप्रदेश का हित होगा।

किसानों की बदहाली के लिए कांग्रेस की गलत नीतियां जवाबदेह -नरेन्द्र सिंह तोमर

6 सितम्बर, 09 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर ने गोहद क्षेत्र में अपनी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में महंगाई और किसानों की बदहाली के लिए कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियां जबावदेह हैं। गोहद क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के जरिए केन्द्र की कांग्रेसनीत यूपीए सरकार को हमें आगाह करना है कि वह विदेशी दवाब अथवा जनविरोधी नीतियों से बाज आए और देश के किसानों, मजदूरों, आम जनता का शोषण बंद करे।

नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी सोबरन जाटव को विजयी बनाने से दोहारा लाभ होगा। कांग्रेस को उसकी गलत नीतियों के लिए दंडित किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाकर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पांच वर्षों में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं की बरसात की है। प्राकृतिक आपदाओं में मिलने वाली राहत को चौगुना किया है। आजादी के बाद कांग्रेस ने उद्योगों के लिए मिलने वाले कर्ज पर ब्याज की दरें घटायीं लेकिन कभी किसान पर लगने वाले ब्याज की दरें कम नहीं की। प्रदेश में भाजपा की सरकार ने किसान के कर्ज पर लगने वाले ब्याज की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत की। बाद में 5 प्रतिशत की और अब 3 प्रतिशत पर किसान को कर्ज दिया जा रहा है। किसान को ऋणग्रस्तता से राहत दिलाना भाजपा का मिशन है। इसके लिए मध्यप्रदेश में किसानी को लाभ का धंधा बनाया जा रहा है। गोहद विधानसभान क्षेत्र की जनता 10 सितंबर को होने वाले चुनाव मदतान में भाजपा को विजयी बनाकर किसानों के हित में की जाने वाली कार्यवाही की गति तेज करेगी। नरेन्द्र सिंह तोमर ने अपना प्रवास एनो से आरंभ कर चन्दोखर, पिपरसाना, निवरन, ईटायदा में सभाएं संबोधित कीं। बाद में गोहद में आयोजित नवमतदाता सम्मेलन में भाग लिया।

आपकी लड़ाई हम लडेंगे - प्रभात झा

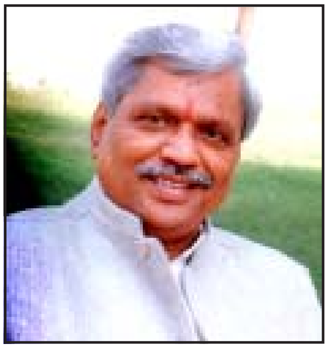

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व सांसद श्री प्रभात झा ने कहा कि चुनाव जीतना या हारना अलग बात है, मनुष्यता का संबंध सबसे बड़ा होता है। संबंध सदैव काम आते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने के कारण हमें सिर्फ आपके वोट ही नहीं बल्कि आपका मन भी चाहिये। आपकी लडाई हम लडेंगे। यह चुनाव सोबरन नहीं बल्कि सारी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है।

उक्त उद्गार भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं सांसद प्रभात झा ने गोहद के प्रबुद्व गहोई वैश्य समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करते हुये व्यक्त किये। बैठक का संचालन समाज के अध्यक्ष डॉ. प्रकाश लोहिया ने किया। बैठक के प्रारंभ में समाज के प्रमुख लोगों ने श्री झा का माल्यार्पण कर स्वागत किया।

श्री झा ने कहा कि गोहद का चुनाव सिर्फ गोहद की जनता के लिये ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान के विकास के प्रति सार्थक दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। ऐसे में गोहद को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये गोहद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सोबरन जाटव को भारी मतों से विजयी बनाये।

इस अवसर पर बाबूलाल पहाडिया, दयाराम कसाव, सुभाष पहाडिया, अनिल पहाडिया, सुनील पहाडिया, अनिल सोनी, राकेश कसाव, रामबाबू डेंगरे, अशोक सांवला, गिरीश चौधरी, अनिल कुमार सोनी, रामशरण गुप्ता, अशोक गेंडा, गौरीशंकर गुप्ता,रामेश्वर लहारिया, रमेशचन्द्र सरावगी, शिवकुमार लिटोरिया, रामजी नीखरा, दमेले जी सहित गहोई वैश्य समाज के अनेक प्रतिष्ठत व्यक्ति उपस्थित थे। ■

मणिपुर की बदहाली के लिए इबोबी सरकार बर्खास्त हो : भाजपा

eणिपुर भाजपा के एक प्रतिनिधिमण्डल ने मणिपुर में विद्रोहियों की गतिविधियों के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए माननीय ग्रहमंत्री, भारत को एक ज्ञापन सौंप कर वहां फैली दुर्दशा से गृहमंत्री को अवगत कराया और उनसे तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इस प्रतिनिधि मण्डल में सर्वश्री डब्ल्यू. निपामाचा सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, मणिपुर, डा. एच. बोरो बाबू सिंह, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, एम. बोरोत सिंह, पूर्वोत्तर सदस्य, भाजपा, प्रकाश जावडेकर, सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता, श्रीमती बिजोय चक्रवर्ती, सांसद शामिल थे।

"अत्यंत विनम्रतापूर्वक तथा आदर सहित भाजपा, मणिपुर की ओर से हम यह ज्ञापन आपके अवलोकनार्थ तथा समुचित कार्रवाई करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं:

पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से मणिपुर निकृष्टतम प्रकार की विद्रोही गतिविधियों का सामना कर रहा है। 30 से भी अधिक विद्रोही समूह यहां लूट–खसोट, हिंसात्मक, अपहरण, हत्या और लूटमार की गतिविधियों में लगे हुए हैं। इन विद्रोही गतिविधियों के कारण राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और राज्य की प्रगति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बदहाली की हालत यहां तक पहुंच गई है कि इन आतंकवादी संगठनों के साथ सख्ती से निपटने की बजाए ऐसा लगता है कि सरकार इनमें से कुछ समूहों के साथ मिलकर काम करने में लगी है। इस प्रकार राज्य में जो भी संभावनाएं है, उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में बेरोजगारी फैलती जा रही है। व्यापार, उद्योग, पर्यटन और वाणिज्य तथा सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां नुकसान उठा रही है। आपकी तत्काल विचारार्थ हम इनमें से कुछ बिन्दुओं का नीचे उल्लेख कर रहे हैं:

- *गैर–मणिपुरी/गैर–स्थानीय लोगों का अपहरण होता है और समय–समय पर उनकी हत्याएं होती रहती हैं।*
- *हिन्दी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाता है।*
- *मणिपुरी नौकरशाही और यहां तक कि कुछ मंत्रीगण भी लूट–खसोट करने वाले संगठनों का साथ देते हैं।*
- *सरकार अपराध–जगत के संगठनों को ठेके देती है।*
- *कुछ मंत्रीगण और विधायकगण तो अपने निजी अंगरक्षकों के रूप में इन विद्रोहियों को नियुक्त करते हैं।*
- *आईबी ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने पीएलए और के.वाई.के.एल को भारी राशि प्रदान की है।*
- *सीनियर आर्मी–जनरल ने यूएनएलएफ से जुड़े एक संगठन को दी गई इस प्रकार की दान राशियों की रसीदें भेजी भी हैं। इस विषय की सूचना गृहमंत्री कार्यालय को दी गई है।*
- *बहुत से विद्रोही मंत्रियों के बंगलों में शरण लेते पाए गए हैं।*
- *म्यांमार की सीमा खुली है और विद्रोही लोग सीमापार से शरण लेने, प्रशिक्षण प्राप्त करने और हथियारों की तस्करी के लिए उपयोग करते रहते हैं।*

विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने इन सारे तथ्यों को सामने भी रखा है।

क्योंकि पुलिसबल की भर्ती में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसलिए स्वाभाविक है कि पुलिस बल का एक बहुत बड़ा हिस्सा लूट–खसोट वाला बन गया है और लोगों को उन पर विश्वास ही नहीं है। इस पृष्ठभूमि में 23 जुलाई की घटना ने राज्य के लोगों के दिलादिमाग को झकझोर कर रख दिया है और वे विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं।

1. *23 जुलाई 2009 को लगभग प्रातः 10.30 बजे खुलेआम इम्फाल की राजधानी के केन्द्र में जो घटना घटी, उसमें श्री चौ. संजीत सिंह की हत्या और एक निर्दोष गर्भवती महिला रबीना देवी और 5 अन्य लोगों की गम्भीर रूप से घायल की घटना ने पूरा पर्दाफाश कर दिया है जिसने पुलिस की "काउण्टर इंमर्जेंसी आप्रेशन" के नाम पर नकली मुठभेड़ के ड्रामे की पोल खोल दी है।*
2. *यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ओ. इबोबी ने जिनके पास गृह मंत्रालय का कार्यभार भी है, सदन को यह कह कर गुमराह किया है कि उग्रवादी संजीत सिंह ने 9 मि. मी. पिस्तौल से रबीना देवी की हत्या की, अन्य 5 लोगों को घायल किया और उसने मौके से भागने की कोशिश की। परन्तु ड्यूटी पर तैनात कमांडो ने वहां तिकेनद्रजीत रोड पर घेरे में डाल लिया और उससे आत्मसमर्पण करने को कहा। अन्ततः उसके द्वारा आत्म समर्पण करने पर उग्रवादी मारा गया। मुख्यमंत्री ने आगे सदन को यह भी बताया कि उसे मारने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा था। अतः सदन ने सर्वसम्मति से इस घटना की निंदा की।*
3. *सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री के बयान के विपरीत 'तहलका.काम' ने पूरी घटना का सिलेसिलेवार पर्दाफाश किया जिसमें बताया गया कि नक्सली मुठभेड़ के नाम पर यह पूरा ड्रामा था जो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। विगत में भी इस प्रकार के कई मामले हुए है परन्तु तकनीकी साक्ष्यों के अभाव में मणिपुर के लोग और इस सम्बंध में बनाए गए जेएसी लाचार बने रहे, हालांकि उन्होंने यह साबित*

करने की कोशिश कि यह सभी घटनाएं नकली मुठभेड़ें थीं। तहलका द्वारा घटना का पर्दाफाश होने के बाद मणिपुर के लोगों ने मुख्यमंत्री श्री ओ.इबोबी के त्यागपत्र की मांग उठाई और राज्य में 'अपूर्व लूप' की 48 घण्टे की आम हड़ताल में लोगों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया।

4. ***सरकार ने सक्रिय रूप से समर्थन करने की बजाए अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया।***
5. ***सरकार ने 2008 में जिन 247 उग्रवादियों के मारे जाने की बात कही है, उसमें से लोगों के विश्वास है कि 100 से अधिक लोग नकली मुठभेड़ में मारे गए और इनके बारे में जांच करने की आवश्यकता है।***
6. ***घटना की न्यायिक जांच की घोषणा और छह कमांडों का निलम्बन कोई पर्याप्त कार्रवाई नहीं है। तहलका के पर्दाफाश किए जाने के बाद यह आवश्यक हो गया है कि सभी दोषियों को धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए और उन्हें तुरंत गिरतार किया जाए।***

भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध है और वह किसी भी अलगाववादी आंदोलन के खिलाफ राष्ट्रीय अखण्डता में विश्वास करती है, परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी नकली मुठभेडों पर मात्र मूक दर्शक बनी रहेगी।

अतः अब भाजपा मणिपुर प्रदेश इस स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए और पिछली कार्रवाई के चलते हमारी मांग है कि–

– ***राज्य में कानून और व्यवस्था तंत्र की पूरी विफलता को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।***
– ***वर्तमान सरकार को तुरंत बरखास्त किया जाए।***
– ***विद्रोहियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए।***
– ***म्यांमार सीमा से हथियारों की तस्करी रोकने के लिए आवश्यक उपाए किए जाएं।***

सादर!''■

हुड्डा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद किए

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

हरियाणा चुनाव को लेकर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 1 सितम्बर को मुख्य चुनाव आयुक्त श्री नवीन बी. चावला से मिला। हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल गुर्जर भी अपने पदाधिकारियों के साथ शामिल थे।

श्री गोयल ने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रतिनिधिमंडल के सामने यह माना कि हुड्डा सरकार जिस तरह से विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही थी, उसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा जल्दी करी है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हुड्डा सरकार ने अपनी सत्ता का दुरूपयोग किया है।

श्री गोयल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की कि हरियाणा की विधान सभा 21 अगस्त को भंग कर दी गई। इसका मतलब अगले चुनाव होने निश्चित थे। उसके बावजूद भी करोड़ों रूपया राजनीतिक, चुनावी लाभ के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरकारी धन का दुरूपयोग करते हुए अपने प्रचार के लिए फूंक डाला। न केवल अखबारों में बल्कि चैनल्स, एफ.एम. रेडियो और विडियो वैन के जरिए जनता के रूपए को राजनीतिक लाभ के लिए खर्च कर दिया गया।

श्री गोयल और श्री गुर्जर ने मांग की कि विधान सभा भंग होने के बाद जितना करोड़ रूपया विज्ञापनों के माध्यम से बर्बाद किया गया, उसका हिसाब मुख्यमंत्री श्री हुड्डा से मांगा जाना चाहिए एवं इसका उद्देश्य अगर राजनीतिक एवं चुनावी लाभ लेना था तो चुनाव आयोग को इसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

श्री गोयल ने कहा कि एक तरफ तो हरियाणा में सूखा पड़ रहा है और राज्य सरकार केन्द्र सरकार से अनुदान मांग रही है और दूसरी तरफ करोड़ों रूपया अपने प्रचार के लिए खर्च किया गया।

श्री गोयल ने कहा कि अभी भी समस्त हरियाणा के अन्दर चुनाव में लाभ लेने के लिए सरकारी होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिन्हें उतारा नहीं जा रहा, जबकि दूसरी ओर धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों के होर्डिंग्स तुरन्त फाड़े जा रहे हैं।

श्री गोयल ने कहा कि यह आचार संहिता के खिलाफ है। आचार संहिता तो उसी दिन लागू हो जानी चाहिए जब विधान सभा भंग होती है, नहीं तो इस खर्चे के लिए गवर्नर या स्टेट इलेक्शन कमिशनर से इजाज़त ली जानी चाहिए। इन सबको देखते हुए हमें यह नहीं लगता कि हरियाणा में निष्पक्ष चुनाव होंगे, इस बारे में राज्य सरकार की भूमिका संदेहास्पद दिखाई देती है।

- अगर विधान सभा भंग ही करनी थी तो यह चुनाव लोक सभा के साथ कराए जा सकते थे, जिससे करोड़ों रूपया बचता। इसलिए चुनाव आयोग को चाहिए कि इस पर विचार करे कि लोक सभा चुनाव के एक साल की अवधि में सरकारें भंग नहीं होनी चाहिए ताकि जनता का पैसा बर्बाद न हो।
- हरियाणा के सभी जिलों को यह आदेश जाना चाहिए कि वे सरकारी सभी होर्डिंग्स एवं अन्य सभी विज्ञापनों को तुरन्त हटाएं।
- हरियाणा में इस बात पर भी नज़र रखनी होगी कि सरकारी गेस्ट हाउस, सरकारी वाहनों एवं अन्य चीजों का दुरूपयोग न हो।
- चुनाव के मद्देनज़र जो नेता या अन्य महत्वपूर्ण लोग हरियाणा में आएं, उनको सुरक्षा देने के मापदण्ड होने चाहिए या फिर चुनाव आयोग की सहमति इसमें होनी चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल में सर्वश्री कृष्णपाल गुर्जर, किशन सिंह सांगवान, श्रीमती सुधा यादव, कैलाश शर्मा, ओमप्रकाश धनखड़ एवं कैप्टन अभिमन्यु शामिल थे।■

मुख्यमंत्री कर रही हैं दिल्ली की जनता का तिरस्कार : मल्होत्रा

fnल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा कि शीला दीक्षित ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से जनता का तिरस्कार करना शुरु कर दिया है। उन्होंने कहा जब 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो सरकार झुग्गी–झोपड़ी और स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों से बिजली उपयोग करने के लिए एक प्वाइंट के 15 रूपए तथा दो प्वांइट के 30 रूपए प्रति माह वसूलती थी।

श्री मल्होत्रा ने कहा कि जब दिल्ली में बिजली वितरण व्यवस्था का निजीकरण किया गया तो उस समय निजी बिजली वितरण कंपनियों ने दादाओं के दम पर झुग्गी–झोपड़ी और स्लम बस्तियों में इलेक्ट्रानिक मीटर लगावाए और उस वक्त मुख्यमंत्री ने झुग्गी–झोपड़ी और स्लम बस्तियों में इलेक्ट्रानिक मीटर लगवाए और उस वक्त मुख्यमंत्री ने झुग्गी–झोपड़ी और स्लम बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों का आश्वस्त किया था वह उन्हें न्यूनतम दर पर बिजली मुहैया कराएंगी। उस समय उन्हें 1.25 रूपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मुहैया कराई जाने लगी।

परन्तु जब वर्ष 2004–05 में बिजली की दरें बढ़ी तो मुख्यमंत्री ने निजी वितरण कंपनियों को सब्सिडी देना प्रारंभ किया, ताकि झुग्गी–झोपड़ी और स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों का बिजली बिल न बढ़े।

उसके बाद जब वर्ष 2005–06 में बिजली की दरें बढ़ी तो मुख्यमंत्री ने न केवल झुग्गी–झोपड़ी और स्लम बस्तियों में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं को बल्कि अन्य क्षेत्र के भी बिजली उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी प्रदान की क्योंकि वह समय चुनाव का वक्त था। मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह करने में कामयाब रही और उसने दिल्ली में सस्ती बिजली के नाम पर वोट बटोरे। परन्तु अब दिल्ली की मुख्यमंत्री का असली चेहरा दिल्ली की जनता के सामने आ गया है और वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 में बिजली की दरों में जो सब्सिडी दी गई थी, वह वापस ले ली गई है। इससे जहां एक तरफ प्रत्येक बिजली उपभोक्ता के बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी हुई है, वहीं झुग्गी–झोपड़ी और स्लम बस्तियों में रहने वाले गरीब और अति गरीब परिवारों के भी बिजली बिल 2.45 रूपए प्रति यूनिट की दर से आना प्रारंभ हो गए हैं और झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के एक महीने का बिजली का बिल 1000 रुपए से अधिक आने लगा है। बिजली के बिलों में एकाएक बेतहाशा वृद्धि से दिल्ली की जनता त्राहि–त्राहि कर रही है। प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में दिल्ली की जनता ने अपने मत के द्वारा इसका जवाब दे दिया है और दो सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में भी दिल्ली की जनता दिल्ली की कांग्रेस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। ■

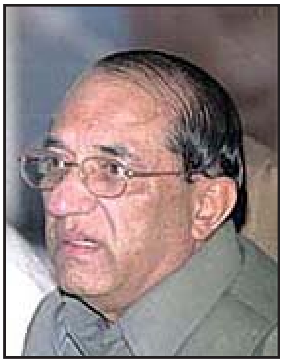

~~~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~~

दोहा बातचीत में कृषि तथा सेवा क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखा जाए : रविशंकर प्रसाद

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा सांसद श्री रविशंकर प्रसाद ने डब्ल्यूटीओ दोहा दौर की प्रस्तावित बातचीत को लेकर कहा कि भाजपा का यह दृढ़ मत है कि जिन करोड़ों भारतीय किसानों की जीविका कृषि पर आधारित है उनके हितों की समुचित रूप से रक्षा की जाए और उनके हितों को आगे बढ़ाया जाए। अनेक विकसित देश, जिनमें अमरीका भी शामिल है, अपने किसानों के हितों का संरक्षण करते हुए कृषि खाद्यान्नों पर बड़ी भारी सब्सिड़ी प्रदान करते हैं। जब तक विकसित देश इस सब्सिडी में सार्थक कमी नहीं करते हैं तब तक हमें टेरिफ कम करने पर क्यों विचार करना चाहिए?

ऐसा कोई संकेत नही मिल रहा है, बल्कि कोई गारण्टी भी नहीं है कि वे इस सब्सिडी को कम करने जा रहे हों। किसी भी तरह भारतीय किसानों के हितों पर आंच नहीं आने दी जानी चाहिए।

श्री प्रसाद ने कहा कि ऐसे और भी सेवा सेक्टर के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे 'बैक अप' कार्यालयों की स्थापना, मानव–जनसंख्या की अदला–बदली आदि, जिसमें भारत की प्रमुख रूचि होगी। हमें इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव की आशा दिखाई नहीं पड़ रही है, अतः भाजपा का आग्रह है कि सरकार को इन क्षेत्रों एवं अन्य विषयों पर बातचीत आगे बढ़ाने से पहले अपने हितों का ध्यान रखना चाहिए। ■
~~~~~~~~~~

चंडीगढ़

'बलरामजी दास टंडन एक प्रेरक चरित्र' पुस्तक का विमोचन

पूर्व उप–प्रधानमंत्री एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने 17 अगस्त को पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री बलरामजी दास टंडन के जीवन पर आधारित पुस्तक 'बलरामजी दास टंडनः एक प्रेरक चरित्र' का विमोचन किया। खचाखच भरे टैगोर थियेटर में आयोजित भव्य समारोह की अध्यक्षता पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने की। इस मौके पर गोवा और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्री केदारनाथ साहनी, पंजाब एवं चंडीगढ़ भाजपा के प्रभारी व सांसद श्री बलबीर पुंज, पंजाब भाजपा के अध्यक्ष प्रो. राजेन्द्र भंडारी, हिंदुस्तान टाइम्स के रेजिडेंट एडिटर श्री रमेश विनायक इस मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि थे।

बलरामजी दास टंडन के पुत्र संजय टंडन द्वारा लिखी गई यह पुस्तक हालांकि श्री टंडन की जीवनगाथा है, लेकिन इसमें पंजाब मामलों की 1957 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक की पूरी जानकारी हैं। पुस्तक में 1980 से 1997 तक पंजाब में चले आतंकवाद के दैर में राजनैतिक परिस्थितियों का विशद वर्णन है। 1967 में जिस प्रकार अकाली–भाजपा सरकार का गठन किया गया और उसके बाद 1969 मध्यवधि चुनाव हुए।

इन चुनाव में अकाली नेता जस्टिस गुरनाम सिंह मुख्यमंत्री और जनसंघ नेता बलरामजी दास टंडन उनके कैबिनेट में वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री बने। पंजाब की राजनीति के दो दिग्गज सरदार प्रकाश सिंह बादल और बलराम जी दास टंडन के एक साथ शुरू हुए राजनीतिक सफर की पूरी कहानी भी किताब में लिखी गई है।

दोनों 1957 में पहली बार विधायक बने। उस समय पंजाब आज के हिमाचल के लाहौल–स्पीति, कुल्लु, मनाली से लेकर हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव और नारनौल तक फैला हुआ था। 1957 के बाद से बादल और टंडन दोनों इकट्ठे जनहित कार्यों में जुटे रहे। बादल सरकार के तीन कार्यकाल 1970–71, 1977–80 और 1997–2002 में बलरामजी दास टंडन को वरिष्ठतम मंत्री का दर्जा मिला।

पुस्तक का विमोचन करने के उपरांत लालकृष्ण आडवाणी ने उत्तर भारत और विशेषकर पंजाब में जनसंघ और उकसे बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए बलरामजी दास टंडन के योगदान की प्रशंसा की। आडवाणी जी ने टंडन जी के लंबे, स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन की कामना की। गौरतलब है कि 'बलरामजी दास टंडनः एक प्रेरक चरित्र' का प्रकाशन चैरिटेबल संस्था कंपीटैंट फाउंडेशन की ओर से किया गया है। यह फाउंडेशन टंडन परिवार के सदस्यों और कंपीटेंट ग्रुप के सदस्यों द्वारा संचालित है। फाउंडेशन की ओर से समय–समय पर गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए कार्य किए जाते हैं। रक्तदान कैंपों का आयोजन, भंडारा लगाना, पीजीआई में आने वाले गरीबों के ऑप्रेशन में मदद करना है तथा झुग्गी बस्तियों के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना कंपीटेंट फाउंडेशन के प्रमुख प्रोजेक्ट हैं।■

छत्तीसगढ

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सशक्त समिति की बैठक

नया रायपुर के विकास के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के साथ विशेष प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। इस विशेष पैकेज के तहत वर्ष 2007.08 में अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि पर 5 प्रतिशत, वर्ष 2008. 09 में अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि पर 10 प्रतिशत तथा वर्ष 2009.10 में अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि पर 20 प्रतिशत विशेष प्रोत्साहन राशि संबंधितों को दी जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि 31 दिसंबर 2009 तक प्राप्त भूमि अधिग्रहण के आवेदनों पर ही दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज शाम यहां मंत्रालय में आयोजित नया रायपुर सशक्त समिति की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवालए .षि मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री केदार कश्यप सहित मुख्य सचिव और नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री पी.जॉय. उम्मेन, प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण श्री एन.बैजेन्द्र कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव श्री अमन कुमार सिंह, गृह निर्माण मण्डल के आयुक्त श्री सुबोध कुमार सिंह तथा नया रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस.एस. बजाज और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नया रायपुर सशक्त समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि नया रायपुर क्षेत्र में आने वाले गांवों में आवश्यकतानुसार दुकानों का निर्माण कर उन्हें स्थानीय जरूरतमंद ग्रामीणों को निर्माण लागत पर दिया जाए। इसके साथ ही नया रायपुर परियोजना के तहत प्रभावित परिवारों के सदस्यों को पुनर्वास हेतु दिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण वृत्ति की राशि को 500 से बढ़ाकर एक हजार प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। बैठक में नया रायपुर क्षेत्र में 13 गांवों में बी.एस.यू.पी. योजना के तहत आर्थिक रूप

से कमजोर वर्ग के लिए बनाए जाने वाले 888 मकानों को निर्माण लागत के 10 प्रतिशत मूल्य पर आवासहीन अनुसूचित जाति, जनजाति तथा विधवा महिलाओं को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि नया रायपुर क्षेत्र में आने वाले गांवों में बनने वाली आवासीय कॉलोनियों का नामकरण उन गांवों के नाम पर किया जाए। बैठक में नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा राज्य शासन के मुख्य सचिव श्री पी.जॉय.उम्मेन ने बताया कि नया रायपुर परियोजना के तहत लगभग आठ हजार हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक छह हजार 223 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है, जिसमें से किसानों की सहमति से 3306 हेक्टेयर भूमि क्रय की गई है। इसके अलावा 2676 हेक्टेयर शासकीय भूमि नया रायपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भूमि अधिग्रहण के कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि केपिटल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत मंत्रालय भवन तथा विभागाध्यक्ष भवन का निर्माण युध्द गति से जारी है। बताया गया कि मंत्रालय भवन का निर्माण मई 2010 तक पूर्ण कर लिया जाएगा तथा उसके पश्चात् आंतरिक साज–सज्जा का कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार विभागाध्यक्ष भवन का निर्माण अक्टूबर 2010 तक पूरा कर उसके पश्चात आंतरिक साज–सज्जा का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने इन भवनों के निर्माण में और अधिक गति लाकर अक्टूबर 2010 तक उनका निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि नया रायपुर क्षेत्र में 67 किलोमीटर सड़कों का निर्माण जारी हैए जो मई 2010 तक पूरा कर दिया जाएगा। नया रायपुर क्षेत्र में गृह निर्माण मण्डल द्वारा शासकीय कर्मचारियों तथा जनसामान्य के लिए बनायी जा रही आवासीय कॉलोनियों की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि इन कॉलोनियों का निर्माण मार्च 2011 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ■

उत्तराखंड

पर्वतीय राज्यों के लिए अलग नीति की मांग

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्र सरकार से पर्वतीय राज्यों के लिए अलग नीति की मांग की है। उन्होंने मांग की कि राज्य में वन और वन उत्पादों को संरक्षित करने के एवज में राज्य को विशेष मुआवजा दिया जाए। निशंक ने कहा कि अगर उत्तराखंड अपने वन क्षेत्रों और उनके उत्पादों का इस्तेमाल करे तो राज्य को कम से कम 1,000 से 1,500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का राजस्व प्राप्त हो सकता है।

उन्होंने कहा कि वनों को संरक्षित रखने में राज्य को अपने गैर योजना मद से धन खर्च करना पड़ता है। निशंक ने कहा कि राज्य के शेष 30 से 35 फीसदी क्षेत्रों के विकास में मुआवजे की राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की अभी भी कमी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई दिल्ली में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया के समक्ष जब राज्य के वार्षिक योजना आकार को स्वी.त करने पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने यह विषय उठाया था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की विशेष भौगोलिक परिस्थिति राज्य की सीमा के नेपाल और चीन से सटे होने और बुनियादी संरचना में कमी को देखते हुए इसकी तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जा सकती।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय राज्यों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में तीन से चार गुना अधिक खर्च आता है। इसलिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त राशि मुहैया करानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य की 375 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से सटी है और 250 किलोमीटर की सीमा नेपाल से जुड़ी है। यह राज्य अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील है। निशंक ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार से उत्तराखंड को पूर्वोत्तर राज्यों की तरह ही विशेष सहायता देने की मांग की है तथा विशेष औद्योगिक पैकेज वर्ष 2020 तक बढ़ाए जाने का आग्रह किया है। ■

हिमाचल प्रदेश

तेरह नए उद्योग मंजूर

राज्य सरकार ने सिंगल विंडो की बैठक में 9 सितंबर को 13 नई औद्योगिक इकाइयों और पांच विस्तार प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में डॉ. रेड्डीज लैब., मैरिको लि., एलएस इंडस्ट्रीज, जेएचएस सेवेंडगाड हाईजीन प्रोडक्टस लिमिटेड, रिसोर्स फूड प्राइवेट लिमिटेड, जॉनसन एंड जॉनसन और बजाज स्टील जैसे प्रमुख औद्योगिक घरानों को उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

इन उद्योगों में 330 करोड़ रुपए का निवेश होगा और प्रदेश के 2017 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धूमल ने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए उपयुक्त माहौल है। वैश्विक मंदी के बावजूद निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक पानी की खपत करने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए परियोजना में जल पुनर्चक्रित प्रणाली को शामिल करें। धूमल ने कहा, यह तय किया जाएगा कि उद्योगों में 70 फीसदी रोजगार हिमाचली लोगों को मिले।

उद्योगमंत्री किशन कपूर ने कहा कि लैंड बैंक स्थापित किया है। संभावित निवेशकों को विकसित प्लॉट उपलब्ध होंगे। इसका मकसद निवेशकों को भू माफिया से बचाना है। मुख्य सचिव आशा स्वरूप ने कहा, प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं में दक्षता उन्नयन के प्रयास किए जाने चाहिए। बैठक में विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव सरोजिनी गंजू ठाकुर, प्रधान सचिव (उद्योग) पी. मित्रा, राज्य विद्युत परिषद के अध्यक्ष सुभाष नेगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भीमसेन, वित्त सचिव अरविंद मेहता, प्रधान सचिव पर्यटन मनीषा नंदा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ■

मध्य प्रदेश : उद्योगों के लिए आकर्षक स्थल

उद्योग के सभी क्षेत्रों की जरूरतों की पूर्ति और मध्य प्रदेश को व्यवसाय के लिए एक आदर्श स्थान बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार 27 अगस्त को मुंबई में ताज होटल में 'इंडस्ट्री इंटरेक्टिव सेशन' का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वे इस मौके पर राज्य में उद्योग के विकास के लिए विचारों का आदान–प्रदान करेंगे। आईटीसी, पारले एग्रो, एचयूएल, गोदरेज, डाबर, अदानी जैसी खाद्य एवं प्रसंस्करण क्षेत्र की कुछ प्रमुख कंपनियों के भी इस अवसर पर उपस्थित रहने की संभावना है। प्रमुख ध्यान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर दिया जा रहा है, क्योंकि देश के सोयाबीन उत्पादन में राज्य की भागीदारी लगभग 60 फीसदी और चना उत्पादन में 40 फीसदी है। मध्य प्रदेश लहसुन और धनिया जैसे मसालों का भी प्रमुख उत्पादक राज्य है। राज्य में गेहूं और आलू की प्रीमियम निर्यात किस्म उपजाई जाती है। भारत में 16 कृषि जलवायु क्षेत्रों में से 11 मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। यहां 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर औषधीय पौधों की दुर्लभ किस्में उपजाई हैं। कृषि और हर्बल क्षेत्र पर ज्ञान पूल मध्य प्रदेश में काफी अधिक है। अपनी जैव विविधता की वजह से राज्य कृषि, हर्बल और बायोटेक क्षेत्रों में निवेश के लिहाज से एक आदर्श जगह है। राज्य में ठेका खेती के लिए निवेश अनुकूल कानूनी ढांचा पहले से चलन में है और इससे हजारों किसान लाभान्वित भी हो चुके हैं।

किसी भी राज्य में यदि विश्वसनीय बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रयास नहीं किए गए हैं तो ऐसे में वहां थोड़ी सी कोशिश भी बेहतर काम कर सकती है। इसका यह अर्थ नहीं कि हर कार्य धीमी रतार से हो और तनाव का विषय बन जाए, बल्कि इसके तहत निवेश बॉडी में प्रतिकूल असर होना ही चाहिए जिससे अन्य लोग भी राज्य में निवेश करने के लिए ामने आएं। देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, मध्य प्रदेश, अपने भौगोलिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कई बोल्ड और निर्णयकारी कदम उठा रहा है। इससे प्रतिदिन के कार्यों में आसानी होती है यहां 1800 कंपनियों और 19 से अधिक औद्योगिक विकास सेंटर चल रहे हैं। यही नहीं यहां छोटे स्तर की 1,71,000 औद्योगिक यूनिट काम कर रही हैं।

मध्य प्रदेश का बुनियादी सुविधाओं का निवेश फंड बोर्ड न केवल राज्य में बुनियादी सेवाओं की योजनाओं के संसाधनों पर नजर रखता है बल्कि पानी की आपूर्ति, सड़क, सिंचाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकासी को भी देखता है। बोर्ड के पास किसी में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का लोन मंजूर करने और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं के लिए अग्रिम मंजूर करने का भी अधिकार है।

> ***मध्य प्रदेश का बुनियादी सुविधाओं का निवेश फंड बोर्ड न केवल राज्य में बुनियादी सेवाओं की योजनाओं के संसाधनों पर नजर रखता है बल्कि पानी की आपूर्ति, सड़क, सिंचाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकासी को भी देखता है।***

यदि कोई वर्तमान स्थिति की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानने की इच्छा रखता है, कोई जानता है कि राज्य मध्य भारत में स्थित है, बिल्कुल उसके हृदय के समान, राज्य का बढ़ी बुनियादी सुविधाएं अधिक नहीं है बल्कि आदर्श के समान हैं। राज्य में सड़कों का विकसित नेटवर्क है, जो देश के ग्रामीण और पर्यटन केन्द्रों को जोड़ता है। राज्य में कुल 72,416 किलोमीटर लंबा सडकों का जाल है। जिसमें से 4676 किलोमीटर सड़कें नेशनल हाइवे के लिए बनाई गई हैं और राज्य हाइवे के लिए इसकी लंबाई 8,333 किलोमीटर है। राज्य के ट्रंक रूट के जरिए दिल्ली–मुंबई, दिल्ली–चेन्नई, दिल्ली–बंगलुरू और दिल्ली–हैदराबाद के रास्ते होकर गुजरते हैं। राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं भोपाल, बीना, ग्वालियर, इंदौर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, रतलाम और उज्जैन। खास बात यह है कि मुख्य रेल मार्ग जो उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ता है, मध्य प्रदेश से होते हुए ही गुजरता है। मंडलीय मुख्यालय भोपाल, रतलाम और जबलपुर में स्थित हैं। राज्य के प्रमुख हवाई अड्डे भोपाल, इंदौर, खजुराहो, जबलपुर और ग्वालियर में हैं और ये देश के प्रमुख शहरों से राज्य को जोड़ते हैं। जहां तक बुनियादी सुविधाओं में संचार की बात है, तो राज्य में हर स्थान पर बेसिक टेलीफोन की सुविधा दी गई है। इसके अलावा 45 जिलों में इंटरनेट टेलीफोनी की सुविधा मुहैया कराई गई। बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल, टाटा इंडिकॉम, रिलायंस और बीएसएनएल राज्य में पहले से ही मौजूद हैं।

जहां तक औद्योगिक बुनियादी संरचना की बात है, तो राज्य में हर स्थान पर बेसिक टेलीफोन की सुविधा दी गई है। इसके अलावा 45 जिलों में इंटरनेट टेलीफोनी की सुविधा मुहैया कराई गई है। राज्य के 18,000 रूटों से होकर एक ऑप्टिकल फाइबर केबल गुजरती है। बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल, टाटा इंडिकॉम, रिलायंस और बीएसएनएल राज्य में पहले से ही मौजूद हैं। जहां तक औद्योगिक बुनियादी संरचना की बात है, तो इंदौर राज्य का प्रमुख व्यवसायिक सेंटरों में से एक है। यही कारण है कि इसे कमर्शियल राजधानी भी कहा जाता है। राज्य में बनाए गए विशेष आर्थिक क्षेत्रों से यहां निवेशक आकर्षित हुए हैं और करीब 200 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश कर चुके हैं। एसईजेड के तहत उद्योग उद्योग जैसे टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल, आटोमोबाइल और सहायक ईकाइयों, धातु विज्ञान और चमड़ा उद्योग को शामिल किया गया है। औद्योगिक विकास के लिए तीन सेंटर बनाए गए हैं। ये पिलुखेड़ी, सतलापुर और मांदीदीप में बनाए गए हैं। ये सभी मध्य प्रदेश के एक अन्य मेट्रो शहर भोपाल से निकट स्थित हैं। इन क्षेत्रों में स्थापित अधिकतर यूनिट कृषि, इंजीनियरिंग और हर्बल क्षेत्र से संबंधित हैं। ■